EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan
Useful For Prelims
Date: 30 December 2025

शनि के उपग्रह टाइटन पर मिल रहे जीवन की संभावनाओं के संकेत

रमेश चंद्रा • जागरण

नैनीताल : किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को लेकर खगोलविदों का शोध-अध्ययन लंबे समय से जारी है।

छोटी-छोटी झीलों से पटी हुई है टाइटन की सतह, इस उपग्रह पर तरल की उपलब्धता जगा रही उम्मीदें

वर्तमान में लाल ग्रह मंगल पर जीवन की तलाश के लिए शोध जारी है। अभी तक दर्जनों मिशन मंगल पर चलाए जा चुके हैं। इसरो भी इस दिशा में निरंतर अपना योगदान दे रहा है। अब शनि के उपग्रह टाइटन की सतह पर झीलों की मौजूदगी की संभावनाओं का पता लगने के बाद विज्ञानी यहां जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। टाइटन पर जीवन की प्रबल संभावनाओं के संकेत मिल रहे हैं।

शनि का उपग्रह टाइटन। सौ. इंटरनेट

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के वरिष्ठ खगोल विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय का कहना है कि ब्रह्मांड में ज्ञात ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन है। इसका विकल्प भी कोई दूसरा ग्रह होना चाहिए वाली सोच के साथ ही खगोलविद वर्षों से शोध अध्ययन में जुटे हुए हैं। इस बीच नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के विज्ञानियों के शोध से पता लगा है कि शनि के उपग्रह टाइटन पर भारी मात्रा में तरल उपलब्ध है। यह जल छोटी-छोटी कई झीलों में मौजूद हो सकता है और इनमें पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक है। इन तालाबों की सतह का तरल जल पोषक तत्वों (न्यूट्रिएंट्स) को ऊपर की ओर ले जाता है। यही प्रक्रिया जीवन की संभावनाओं को अधिक बल देती है।

शनि ग्रह पर मौजूद नासा के कैसिनी यान से जुटाए आंकड़ों के आधार पर यह शोध संभव हुआ है। अब नासा अगला रोवरक्राफ्ट मिशन ड्रैगनफ्लाई लांच करने की तैयारी में जुट गया है। जिसे 2028 में लांच किए जाने की योजना प्रस्तावित है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अगले कुछ सालों में आर्टेमिस मिशन के जरिये मानव दल को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की तैयारी में भी है।

बुध ग्रह से भी बड़ा है टाइटन

डा. शशिभूषण पांडेय के अनुसार शनि के उपग्रह टाइटन का आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किमी है। इसका अपना घना वायुमंडल है। इसकी सतह पर मीथेन और इथेन गैस मौजूद है। यहां पर झीलों के अलावा समुद्र भी हैं। यह कई मायनों में पृथ्वी के समान है। जिस कारण इस उपग्रह पर जीवन की प्रबल संभावनाएं है।

Dainik Jagaran Page No-14

समोआ और टोकेलाऊ में नहीं आई 30 दिसंबर की तिथि

2011 में दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों समोआ और टोकेलाऊ अपने व्यापारिक साझेदारों (आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के साथ तालमेल बिठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बदलकर एक दिन आगे बढ़ गए थे। 29 के बाद उन्होंने सीधा 31 दिसंबर में प्रवेश किया।

संधि पर हस्ताक्षर कर की गई सोवियत संघ की स्थापना

1922 में आज ही रूस, यूक्रेन, बेलारूस व ट्रांसकाकेशियन सोवियत गणराज्यों के प्रतिनिधियों ने मास्को में एक संधि पर हस्ताक्षर कर सोवियत संघ की स्थापना की थी। इससे दुनिया का पहला मार्क्सवादी समाजवादी राष्ट्र बना। इसे 1924 के सोवियत संविधान द्वारा कानूनी रूप दिया गया।

मप्र के जंगलों से प्रेरणा लेकर किपलिंग ने गढ़ा था मोगली का किरदार

रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में आज ही बांबे (अब मुंबई) में हुआ था। छह साल की उम्र में उनके माता-पिता उन्हें इंग्लैंड ले गए और पालक घर में रखा। इस दौरान अपने साथ हुए बुरे बर्ताव का वर्णन उन्होंने कहानी 'बा बा, ब्लैक शीप (1888)' में किया था। 1882 में भारत लौटे और कविताएं व कहानियां लिखने लगे। 1894 में प्रकाशित कहानी संग्रह द जंगल बुक ने उन्हें विश्वभर में प्रसिद्धि दिलाई। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के जंगल इस कृति की वास्तविक पृष्ठभूमि माने जाते हैं। इसका किरदार मोगली भेड़ियों के साथ रहने वाले असली बच्चे की कहानियों और किंवदंतियों से प्रेरित है।

Dainik Jagaran Page No-14

तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने से खटास | कूटनीति | ढाका की पहल ने क्षेत्रीय समीकरणों को बनाया जटिल

बांग्लादेश से बढ़ा तनाव, आगे संबंध सुधरने की उम्मीद

ढाका, 29 दिसंबर (भाषा)।

राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोपों से जूझते बांग्लादेश के भारत के साथ संबंधों में इस साल गिरावट आई और दोनों पड़ोसी देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी बढ़ी। पिछले वर्ष अगस्त में सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने और भारत चले जाने के बाद रिश्तों में खटास आई। प्रदर्शनों के दौरान हिंसक कार्रवाई में कथित भूमिका के लिए इस वर्ष एक न्यायाधिकरण ने हसीना की अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई।

ढाका ने भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को विभिन्न मुद्दों पर पांच बार तलब किया, जबकि भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त

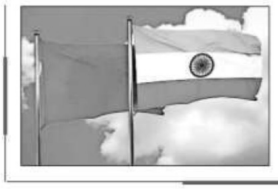

यूनुस ने भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का वादा किया था लेकिन हाल के महीनों में अंतरिम प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी चर्चा में रहे। वर्ष के अंत में राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक संकट और अपने निकटतम पड़ोसी भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों से जूझता बांग्लादेश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

रियाज हामिदुल्ला को एक बार बुलाया और उनके देश में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताई। व्यापक रूप से 'भारत-हितैषी' मानी जाने वाली अवामी लीग सरकार से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में हुए परिवर्तन ने बांग्लादेश के कूटनीतिक रुख को काफी हद तक बदल दिया। वहीं, इस्लामाबाद के साथ रिश्ते गहरे करने की ढाका की पहल ने क्षेत्रीय समीकरणों को और जटिल बना दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ बड़ी वैश्विक ताकतों की सीमित दिलचस्पी के कारण बांग्लादेश की स्थिति और कठिन हुई तथा ढाका कूटनीतिक रूप से दिशाहीन हो गया।

विश्लेषकों ने निर्वाचित सरकार के अभाव के कारण 2025 को बांग्लादेश के लिए 'गायब साल' करार दिया, जहां प्रमुख दूतावासों का संपर्क अंतरिम प्रशासन की तुलना में अगली सरकार बनाने की संभावना वाले दलों से अधिक रहा।

पूर्व राजदूत महफूजुर रहमान ने कहा कि 2025 में बांग्लादेश 'किसी स्पष्ट विदेश नीति दिशा' के बिना आगे बढ़ा। द्विपक्षीय रिश्तों में आए तनाव को दूर करने में दिल्ली की ओर से नरमी और परिपक्वता के संकेत दिखे, लेकिन ढाका ने रिश्ते सुधारने की बजाय और जटिल बनाया।' ढाका ने इसके बजाय एक अपरिपक्व रवैया दिखाया, जो साफ तौर पर एक घरेलू वर्ग को खुश करने के लिए था।' वर्ष के अंतिम महीनों में भारत-विरोधी ताकतों के उभार ने क्षेत्र में चिंता बढ़ाई। साथ ही, आम चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 घोषित होने के बाद राजनीतिक हिंसा में वृद्धि देखी गई।

Jansatta Page No-18

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा

यूक्रेन और रूस शांति समझौते के करीब

पाम बीच, 29 दिसंबर (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के पहले से कहीं अधिक करीब हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने रिजार्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए यह बयान दिया लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वार्ताएं जटिल हैं और इनके विफल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता जिससे युद्ध वर्षों तक खिंच सकता है। ट्रंप ने ये बयान दोनों नेताओं की बातचीत के बाद दिए।

ट्रंप ने कहा कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी फोन पर ढाई घंटे बहुत अच्छी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन अब भी शांति चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की के

वार्ता के लिए अमेरिका रवाना होने के बीच रूस ने यूक्रेन पर फिर हमले किए।

ट्रंप और जेलेंस्की ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई जटिल मुद्दे अब भी बाकी हैं जिनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों का क्या होगा और यूक्रेन के लिए ऐसे सुरक्षा आश्वासन कैसे सुनिश्चित किए जाएं कि भविष्य में उस पर फिर हमला न हो। इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने यूरोप के कई नेताओं से भी फोन पर बात की जिनमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन के साथ-साथ फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के नेता शामिल थे।

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप जनवरी में यूरोपीय नेताओं की एक और बैठक की मेजबानी पर सहमत हुए हैं जो संभवतः वाइट हाउस में होगी। ट्रंप ने कहा कि बैठक वाशिंगटन में या 'कहीं और' भी हो सकती है। जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, 'यूक्रेन शांति के लिए तैयार है।' ट्रंप ने कहा कि वह जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से एक बार फिर फोन पर बात करेंगे। इससे पहले रविवार को पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन वार्ता की पहल अमेरिका की ओर से हुई थी और बातचीत 'मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और काम-काज संबंधी' रही।

Jansatta Page No-18

विश्व परिक्रमा

पाकिस्तान : अभी भी हैं 20 लाख अफगान शरणार्थी

जनसत्ता संवाद

पाकिस्तान से वर्ष 2025 में 10 लाख से अधिक लोगों के स्वदेश लौटने के बावजूद वहां अब भी 20 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजंसी (यूएनएचसीआर) ने यह रपट दी है।

संरा के मुताबिक, केवल नवंबर महीने में ही 1,71,055 अफगान नागरिक अपने देश लौटे, जिनमें से 37,899 को चमन, तोरखम और बाराबचा सीमाओं के जरिये निर्वासित किया गया। इसी महीने यूएनएचसीआर के प्रत्यावर्तन केंद्रों के माध्यम से 31,500 से अधिक 'प्रूफ आफ रजिस्ट्रेशन' (पीओआर) कार्डधारकों को भी अफगानिस्तान भेजा गया। नवंबर में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव के कारण

मानवीय सहायता कार्यों में बाधा आई और सीमा पार आवाजाही प्रतिबंधित रही। खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में 'अवैध विदेशी प्रत्यावर्तन योजना' (आइएफआरपी) के तीसरे चरण के कड़े कार्यान्वयन के बावजूद, यूएनएचसीआर और उसके सहयोगियों ने आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित कीं। इनमें महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के लिए सुरक्षा के साथ-साथ कानूनी और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जारी रखना शामिल है। पाकिस्तान सरकार ने सितंबर 2023 में आइएफआरपी योजना शुरू की थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर अफगानों की वापसी शुरू हुई।

योजना के पहले (सितंबर 2023) और दूसरे (अप्रैल 2025) चरण में बिना दस्तावेजों वाले अफगानों और 'अफगान नागरिकता कार्ड' धारकों को लक्षित किया गया था। जुलाई 2025 तक इन चरणों के तहत शहरी क्षेत्रों और शरणार्थी गांवों से 11 लाख से अधिक अफगान वापस जा चुके थे। सितंबर 2025 में शुरू हुए तीसरे चरण में अब तक करीब 1.66 लाख 'पीओआर' कार्डधारक लौटे हैं।

Jansatta Page No-7

एलआरजीआर ने सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा

लंबी दूरी के 'पिनाका' राकेट का पहला परीक्षण सफल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर ।

पिनाका श्रेणी में लंबी दूरी के निर्देशित राकेट का पहला परीक्षण सोमवार को सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। इसने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद दिया। यह परीक्षण ओड़ीशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (आइटीआर) में आयोजित किया गया।

योजना के अनुरूप, राकेट का परीक्षण 120 किलोमीटर की इसकी अधिकतम मारक क्षमता के संदर्भ में किया गया। मंत्रालय ने कहा कि 'पिनाका लांग रेंज गाइडेड राकेट' (एलआरजीआर 120) का पहला परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक किया गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एलआरजीआर ने सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने का प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बताया कि एलआरजीआर को सेवा में मौजूद 'पिनाका लांचर' से दागा गया, जिससे इसकी बहुआयामी विशेषता का प्रदर्शन हुआ और एक ही 'लांचर' से अलग-अलग दूरी के पिनाका संस्करण को दागने की क्षमता साबित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के निर्देशित राकेटों के सफल डिजाइन और विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। सिंह ने इसे 'बाजी पलटने वाला' करार दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को बधाई दी। कहा कि लंबी दूरी के निर्देशित राकेटों के सफल डिजाइन और विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। सिंह ने इसे 'बाजी पलटने वाला' करार दिया है।

Jansatta Page No-16

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दो साल के उच्च स्तर 6.7 फीसद पर

नई दिल्ली, 29 दिसंबर (भाषा)।

खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 फीसद पर पहुंच गई। यह जानकारी सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में दी गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) नवंबर, 2024 में पांच फीसद बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 फीसद दर्ज किया गया था। त्योहारों से पहले देश में मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में 22 सितंबर 2025 से कटौती की गई थी। इससे जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण आर्डरों में तेजी आई। इसके साथ एनएसओ ने अक्तूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। अक्तूबर के लिए आइआइपी वृद्धि को बढ़ाकर 0.5 फीसद कर दिया गया है जबकि पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान 0.4 फीसद का था।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन आठ फीसद बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.5 फीसद था। खनन क्षेत्र का उत्पादन भी नवंबर में 5.4 फीसद बढ़ा जबकि नवंबर 2024 में यह वृद्धि 1.9 फीसद रही थी।

Jansatta Page No-16

व्यक्तित्व

युवराज संधू: गोल्फ के एक सत्र में सात खिताब जीतने का कीर्तिमान

जनसत्ता संवाद

भारतीय गोल्फ के युवा सितारे युवराज संधू ने टाटा ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीतकर पीजीटीआइ के एक सत्र में सबसे ज्यादा खिताब जीतने का नया कीर्तिमान बनाया। चंडीगढ़ के 28 वर्षीय युवराज संधू ने घरेलू सीजन में 19 प्रतियोगिताओं में से सात में जीत हासिल की है। पीजीटीआइ आर्डर आफ मेरिट में शीर्ष स्थान हासिल करने के कारण उन्होंने 'डीपी वर्ल्ड टूर 2026' के लिए प्रवेश हासिल कर लिया है, जहां वे गोल्फर शुभंकर शर्मा के साथ खेलेंगे। युवराज ने रविवार को 'टाटा ओपन टूर्नामेंट' के रोमांचक खिताबी मुकाबले में आखिरी होल पर मैच जीतने वाले बर्डी के दम पर एक शाट के अंतर से ट्राफी पर कब्जा जमाया।

अंतिम दौर में उन्होंने 6-अंडर 65 का शानदार अंक हासिल किया। चार दौर में उन्होंने 67-64-68-65, कुल 20-अंडर 264 का अंक हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर 15 फीट की बर्डी पुट सफलतापूर्वक डाली। इस जीत के साथ उन्होंने मनु गंडास के 2022 के छह खिताबों का कीर्तिमान तोड़ दिया। विजेता के तौर पर उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम मिला। इसी के साथ इस सीजन में उनकी कुल कमाई 1,91,67,100 रुपए हो गई। उन्होंने इसी के साथ वीर अहलावत (1,56,35,724 रुपए) के पीजीटीआइ पर सीजन की कमाई का पिछला रेकार्ड तोड़ दिया।

जीत के बाद युवराज ने कहा, 'जीत से मदद मिलती है। लेकिन मुझे अहसास है कि मानसिक रूप से सुरक्षित रहना सफलता की कुंजी है। जीत और हार दोनों ने ही मुझे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। मैंने अपनी जीत का हिसाब रखा। अपने काम में बेहतर करने की इच्छा ने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया है।' टाटा ओपन टूर्नामेंट जमशेदपुर के बेलडीह और गोलमुरी गोल्फ कोर्स पर खेला गया, जहां पहले दो दौर में आधे खिलाड़ी एक कोर्स पर और आधे दूसरे पर खेले। युवराज ने कहा, 'इस सत्र को अच्छे प्रदर्शन से खत्म करने का इरादा था और मैंने ऐसा कर दिखाया। शुभम ने अंत तक कड़ी टक्कर दी। मेरे लिए सात खिताब जीतना खास है। इस साल मैंने कुछ अहम उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जैसे दिल्ली गोल्फ क्लब में जीत और टाटा ओपन जीतना। अब अगले वर्ष डीपी वर्ल्ड टूर पर खेलने के लिए उत्साहित हूं।' युवराज अगले महीने दुबई में आयोजित डेजर्ट क्लासिक में अपने पहले 'डीपी वर्ल्ड टूर सीजन' की शुरुआत करेंगे। इसके बाद कतर मास्टर्स खेला जाएगा। फिर बहरीन में टूर्नामेंट होगा। नए साल की पहले छमाही में केन्या, गुरुग्राम और चीन में स्पर्धाएं होंगी।

सम-सामयिक

म्यांमा : आम चुनावों को लेकर उठने लगे सवाल

जनसत्ता संवाद

म्यांमा में हुई उथल-पुथल ने भारत के उत्तरपूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया है। वहां फरवरी 2021 में तख्तापलट हुआ था। इसका वीडियो अनजाने में फिल्माया गया था। म्यांमा की राजधानी में एक व्यायाम प्रशिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें काले रंग की बख्तरबंद गाड़ियां संसद की ओर जाती हुई दिखाई दे रही थीं, और अनजाने में ही महिला ने तख्तापलट की शुरुआत को फिल्मा लिया था।

लोकतांत्रिक शासन के अंत का प्रतीक रहे उस तख्तापलट के बाद पहली बार, म्यांमा में रविवार (28 दिसंबर) से चुनाव शुरू हुए। हालांकि, सामान्य स्थिति की वापसी के संकेत के रूप में देखे जाने के बजाय, कई अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2021 से अब तक 30,000 से अधिक राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के सदस्य और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके कुछ प्रतिनिधियों ने तो चुनावों को ढोंग तक कह दिया है।

म्यांमा ने 1948 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कई राजनीतिक अस्थिरता के दौर देखे। 1962 में, लोकतांत्रिक सरकार को सैन्य शासन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। वर्ष 2011 में एक बड़ा बदलाव आया, जब सेना ने धीरे-धीरे सैन्य-प्रभुत्व वाली नागरिक संसद की ओर जाने की अनुमति दी। थिंक टैंक 'काउंसिल आन फारेन अफेयर्स' ने लिखा कि पूर्व सैन्य अधिकारी थेन सीन को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया और उन्होंने मीडिया सेंसरशिप में ढील देने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने सहित कई सुधारों का नेतृत्व किया।

इससे नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी (एनएलडी) की नेता आंग सान सू ची के लिए राजनीतिक नेतृत्व की प्रबल दावेदार के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त हुआ। हालांकि उन्हें 1989 से 2010 तक नजरबंद रखा गया, फिर भी विदेशों में उन्हें शांति और लोकतंत्र की पैरोकार के रूप में सराहा गया। वर्ष 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

भरोसे का संकट

तख्तापलट के बाद पहली बार, म्यांमा में रविवार (28 दिसंबर) से चुनाव शुरू हुए। कई अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2021 से अब तक 30,000 से अधिक राजनीतिक विरोधियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के सदस्य और राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। इस उथल-पुथल का सीधा असर भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर पड़ा है।

वर्ष 2015 में आम चुनाव हुए, जिनमें एनएलडी और सेना की सहयोगी पार्टी, यूनियन सालिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) मुख्य उम्मीदवार थीं। एनएलडी ने आसानी से जीत हासिल की। शुरुआत में कुछ लोगों का तर्क था कि वह एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हैं, जो जटिल इतिहास वाले बहुजातीय देश पर शासन करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सेना की कार्रवाई का उनका व्यक्तिगत बचावह्न उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक नया मोड़ साबित हुआ। इसका असर 2020 के चुनावों में भी दिखा, जिसमें एनएलडी ने जीत हासिल की, लेकिन सेना ने 2021 के तख्तापलट को जायज ठहराने के लिए चुनावों में धांधली का आरोप लगाया। हालांकि, उनकी अप्रत्यक्ष चिंता एनएलडी द्वारा संविधान में संभावित बदलाव को लेकर थी। सू ची और अन्य एनएलडी नेताओं को जेल भेज दिया गया और वरिष्ठ जनरल मिन आंग ने सत्ता संभाली।

तख्तापलट के परिणामस्वरूप नवगठित सैन्य जुंटा (जिसे आधिकारिक तौर पर राज्य प्रशासन परिषद नाम दिया गया था) को पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली।

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा संबंधी मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्देशों को स्थगित किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने 20 नवंबर के पहले के निर्देशों पर सोमवार को रोक लगा दी। अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने यह चिंता भी जताई कि विशेषज्ञ समिति की रपट और अदालत की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है।

पीठ ने कहा कि कुछ महत्त्वपूर्ण अस्पष्टताओं को दूर करने की आवश्यकता है, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का अंतर पर्यावरण संरक्षण के दायरे के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को कम कर देगा। पीठ ने कहा कि रपट या कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की जरूरत है। पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले पर 21 जनवरी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि समिति की सिफारिश और इस कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाना जरूरी है। समिति के गठन तक रोक जारी रहेगी। यह स्वतः संज्ञान मामला इस चिंता के बाद शुरू किया गया था कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में हालिया बदलाव से बिना रोक-टोक खनन और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। पीठ ने कहा कि लागू करने से पहले निश्चित मार्गदर्शन देने के लिए एक निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय पर विचार किया जाना चाहिए। पीठ ने इस

पीठ ने कहा कि कुछ महत्त्वपूर्ण अस्पष्टताओं को दूर करने की आवश्यकता है, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का अंतर पर्यावरण संरक्षण के दायरे के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को कम कर देगा। पीठ ने कहा कि रपट या कोर्ट के निर्देशों को लागू करने से पहले और स्पष्टीकरण की जरूरत है। पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले पर 21 जनवरी को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।

बात की जांच करने की जरूरत बताई कि क्या अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा ने बाकी पेज ८ पर

सरकार अरावली के संरक्षण और बहाली के लिए प्रतिबद्ध : भूपेंद्र यादव
अरावली की नई परिभाषा की वकालत करने वाले भूपेंद्र यादव तत्काल इस्तीफा दें : कांग्रेस
पेज 8

Jansatta Page No-1

अरावली विमर्श

अरावली की रक्षा के लिए होने वाला हर प्रयास स्वागतयोग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की रक्षा के लिए अपने ही पूर्व के फैसले पर रोक लगाकर बहुत सकारात्मक माहौल बना दिया है। दरअसल, 20 नवंबर को न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को सीमित करके देखा जा रहा था। अब न्यायालय ने एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाकर उचित फैसला लिया है। इस पूरे क्षेत्र में खनन संबंधी नियमों को दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि नियमों में ढिलाई हुई, तो फिर अरावली की रक्षा नहीं हो सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय को अरावली संबंधी नियमों के पुनर्विचार पर पूरी दृष्टि रखनी पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यापक विषय है, जिसे सामान्य ढंग से बरतने के बड़े नुकसान हैं। जाहिर है, न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर न्यायमूर्ति निर्णय सुनाते हैं। अरावली ऐसा विषय है, जिसमें कदम-कदम पर तथ्यों की पड़ताल जरूरी है। ऐसे में, यह बहुत सराहनीय है कि अरावली की उपेक्षा संबंधी शिकायतों का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।

बहरहाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की पीठ का रुख स्पष्ट है। अब न्यायालय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से तमाम पहलुओं की विस्तृत जांच करेगा। एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन होगा। यहां निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र राय की आवश्यकता है। लक्ष्य केवल एक ही है और होना चाहिए कि किसी भी तरह से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद संबंधित सरकारी विभागों को बेहद सचेत भाव से चलना होगा। अरावली का मानचित्रण और सीमांकन जैसे काम अब न्यायालय की निगाह में आ जाएंगे। संभव है, इससे अरावली संबंधी नए तथ्य सामने आएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरावली को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई जगह इसके पहाड़ों को काटा-छांटा गया है। यह ध्यान देने की बात है कि एक पहाड़ अगर जमीन से ऊपर होता है, तो उसका फैलाव जमीन के अंदर भी होता है। किसी पहाड़ को जब काटा जाता है, तब उसकी नींव भी खोद दी जाती है। ऐसा अरावली की पहाड़ियों के साथ अनेक जगहों पर हुआ है, अतः खनन की स्वतंत्र पड़ताल आवश्यक है। उम्मीद करनी चाहिए कि अरावली संबंधी जो नियम-कायदे अब सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में बनेंगे, उनकी पालना सुनिश्चित होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली संबंधी अपने पूर्व के फैसले पर रोक लगा दी है। अब नए सिरे से अरावली की समीक्षा होगी, ताकि कहीं भी पर्यावरण से खिलवाड़ न होने पाए।

इस पूरे प्रकरण में एक तथ्य यह भी है कि सरकार ने पूर्व में आए आदेश की कमियों को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही का स्वागत करते हुए माना है कि नवंबर के फैसले पर कई गलतफहमियां हैं। सरकार इस बात से सहमत है कि अब सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद ही खनन या अरावली संबंधी कोई नियम लागू होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह पर गौर करने की जरूरत है। खनन व्यापार का विषय है, उसे पूरी तरह से शायद नहीं रोका जा सकता, लेकिन खनन ऐसा न हो कि लोगों की जान पर बन आए। प्रकृति ने हमें जो पहाड़-पर्वत दिए हैं, उनका लाभ हम सदियों से उठाते आ रहे हैं। इस प्राकृतिक लाभ से हमें वंचित नहीं होना चाहिए। न्यायालय अरावली की रक्षा अवश्य करेगा, लेकिन यहां आम लोगों को भी सजग रहना होगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की जानलेवा लूट को रोका जा सके।

Hindustan Page

अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा वाले अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सीजेआइ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा-कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण की है आवश्यकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा और 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर उठे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ही फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें स्वीकार करने वाले अपने 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल टालते हुए कहा कि कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने और मामले की जांच की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और आगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने मामले की जांच करने और खामियों को दूर कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बगैर किसी प्रकार के खनन को इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार व दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा।

दिए प्रस्ताव और निर्देश

- एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित कर मामले की गहनता से जांच कराने का दिया प्रस्ताव
- शीर्ष अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर किसी प्रकार के खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी

किसी भी नियामकीय खामी पर आगे की जांच जरूरी

शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा कि पर्यावरणविदों ने नई परिभाषा और कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या व अनुचित कार्यान्वयन की आशंका जताते हुए चिंता प्रकट की है। यह आलोचना या असहमति कोर्ट के निर्देशों में स्पष्टता की कमी से उत्पन्न होती है। इसलिए अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता को कमजोर करने वाली किसी भी नियामकीय खामी को रोकने के लिए जांच और स्पष्टीकरण की सख्त आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा-इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण जरूरी

- क्या अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की परिभाषा, जो विशेष रूप से दो या दो से अधिक पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित है, एक संरचनात्मक विरोधाभास पैदा करती हैं? इससे संरक्षित क्षेत्र का भौगोलिक दायरा संकुचित हो जाता है। क्या इस सीमांकन ने गैर अरावली क्षेत्रों के दायरे को विस्तृत कर दिया है, जिससे अनियमित खनन और अन्य विघटनकारी गतिविधियों को जारी रखने में सुविधा हो रही है?
- क्या 100 मीटर और उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियां निर्धारित 500 मीटर की सीमा से अधिक की दूरी होने पर भी, एक सन्निहित पारिस्थितिक संरचना का गठन करती हैं। व्यापक रूप से प्रचारित आलोचना कि राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1048 पहाड़ियां ही 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा को पूरा करती हैं, जिससे शेष निचली पहाड़ियों को पर्यावरण संरक्षण से वंचित कर दिया जाता है, क्या यह तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से सही है?

शीर्ष अदालत ने यह आदेश मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर की गई सुनवाई के दौरान दिया। सुप्रीम कोर्ट के गत 20 नवंबर के आदेश में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था। एक विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू-आकृति को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है, लेकिन समान परिभाषा न होने के कारण राज्यों ने अपने-अपने मानदंड और परिभाषाएं बनाई हैं। इस मामले में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने खनन के संदर्भ में अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की कमेटी द्वारा सुझाई गई परिभाषा को स्वीकार कर लिया था।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय हर सहयोग देने को तैयार : भूपेंद्र यादव पेज>>5

अरावली के साथ खोद डाले 7000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष

निर्लोष कुमार • जागरण

- फतेहपुर सीकरी स्थित अरावली पहाड़ियों पर राक शेल्टर्स में बनी हैं राक पेंटिंग्स
- सात दशक पहले खोजा गया था इन्हें, तब से लेकर अब तक इनका संरक्षण नहीं कर सका पुरातत्व विभाग

आगरा : खनन माफियाओं ने अरावली के साथ इन पहाड़ियों में दर्ज सात हजार साल पुरानी सभ्यता के अवशेष को भी नष्ट कर दिया है। फतेहपुर सीकरी के भदरौली, रसूलपुर, पतसाल व मदनपुरा (जाजौली) गांव के पास अरावली की चट्टानों पर बने प्राकृतिक आवासों की छतों पर प्रागैतिहासिक शैल चित्र (राक पेंटिंग्स) बने हुए हैं। वह युग जब मनुष्य ने पहले पहल चट्टानों में आवास बनाकर रहना शुरू किया। खनन से सभ्यता के ये अधिकांश अवशेष नष्ट हो गए हैं। सात दशक पहले इन्हें खोजा गया था। तब से लेकर अब तक पुरातत्व विभाग इनका संरक्षण नहीं कर सका।

एएसआइ संरक्षित स्मारक फतेहपुर सीकरी से करीब चार-पांच किमी की दूरी पर स्थित राक शेल्टर्स (शैलाश्रय) में राक पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यह लाल, गेरू और काले रंग में बनी हैं और उत्तर पाषाण काल (7000 वर्ष पहले) से लेकर गुप्त काल (तीसरी शताब्दी) तक की मानी जाती हैं। इनमें हिरण, मवेशी, कूबड़ वाला बैल, बंदर, बाघ, शेर, बिल्ली आदि जानवरों के चित्र शामिल हैं। खनन माफियाओं में इस क्षेत्र में कई किलोमीटर तक खनन करके अरावली की विस्तारित व अवशेष पहाड़ियों को समतल कर दिया है। रसूलपुर, मदनपुरा व पतसाल में अभी कुछ चित्र बचे हुए हैं। स्थानीय लोगों के खनन के कारण बचे हुए शैलचित्रों के भी नष्ट होने का खतरा है।

एएसआइ के आगरा कार्यालय से इनके संरक्षण को पूर्व में कुछ प्रयास किए गए। एएसआइ की तकनीकी मूल्यांकन समिति की 28 अप्रैल, 2023 को हुई बैठक में समिति ने राक शेल्टर्स के संरक्षण को प्रस्तावित क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करने की सिफारिश की। राक शेल्टर्स के संरक्षण को प्रयासरत डा. देवाशीष भट्टाचार्य ने कहा कि तकनीकी मूल्यांकन समिति ने प्रस्तावित क्षेत्र के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लिया था। एएसआइ को इसका संरक्षण तुरंत करना चाहिए, अन्यथा वह धीरे-धीरे नष्ट हो जाएंगी।

1959 में प्रकाशित हुआ था शोध पत्र

फतेहपुर सीकरी की राक पेंटिंग्स पर वर्ष 1959 में शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। राक आर्ट सोसायटी आफ इंडिया के सचिव पुरातत्वविद् डा. गिरिराज कुमार ने रसूलपुर में 12, मदनपुरा में तीन और पतसाल में चार राक शेल्टर्स की खोज की थी। जून, 2023 में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने फतेहपुर सीकरी स्थित राक शेल्टर्स का निरीक्षण किया था। अधीक्षण पुरातत्वविद् डा. स्मिथा एस. कुमार ने बताया कि फतेहपुर सीकरी स्थित राक शेल्टर्स में बनी राक पेंटिंग्स के संरक्षण के प्रस्ताव का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। पांच जनवरी के बाद फतेहपुर सीकरी की राक शेल्टर्स की विजिट की जाएगी।

मंत्रालय हर सहयोग देने को तैयार : भूपेंद्र यादव

जागरण, नई दिल्ली : अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर की नई परिभाषा संबंधी अपने आदेश पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि अरावली पर्वतमाला की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यादव ने कहा कि मंत्रालय अरावली की सुरक्षा के लिए गठित होने वाली नई समिति को पूरा सहयोग देने को तैयार है। मौजूदा स्थिति के अनुसार, अरावली में नए खनन पट्टे या पुराने खनन पट्टे के नवीनीकरण पर पूरी तरह से रोक जारी है। अरावली पर्वतमाला की जिस नई परिभाषा पर यह विवाद खड़ा हुआ है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित एक विशेषज्ञ कमेटी ने तैयार किया था। प्रेट्र के अनुसार, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि नई परिभाषा के पक्ष में उनके सभी तर्क खारिज कर दिए गए हैं।

Dainik Jagaran Page No-7

अब नए सिरे से तैयार होगी अरावली की परिभाषा

नई दिल्ली, प्रेट्र : दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली को लेकर केंद्र सरकार की नई परिभाषा और उसके पर्यावरणीय प्रभावों पर विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर रोक लगानी पड़ी, यहां समझिए पूरा मामला।

विवाद आखिर है क्या?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति ने अक्टूबर में अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा सुझाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सोमवार को अदालत ने अपने आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित (अबेयेंस) कर दिया। इसी नई परिभाषा को लेकर राजनीतिक और पर्यावरणीय विवाद खड़ा हुआ है।

समिति ने क्या सिफारिश की थी?

समिति के अनुसार, अरावली जिलों में स्थित कोई भी भू-आकृति जो स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हो, उसे "अरावली हिल" माना जाए। वहीं, 500 मीटर के भीतर स्थित दो या अधिक ऐसी पहाड़ियों के समूह को "अरावली रेंज" की संज्ञा दी जाए। इसमें पहाड़ी के सहायक ढलान और उससे जुड़े भू-आकृतियों को भी शामिल करने की बात कही गई थी।

खनन पर क्या रोक लगाई गई थी?

20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने पर रोक लगा दी थी, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक लागू होती है। बाद में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए मंत्रालय ने भी नई खनन लीज पर प्रतिबंध की घोषणा की।

नई परिभाषा में भी कौन-से इलाके सुरक्षित रहते?

टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, इको-सेंसिटिव जोन, वेटलैंड्स और क्षतिपूरक वनीकरण के तहत आने वाले क्षेत्र पहले की तरह संरक्षित रहते। इन इलाकों में खनन या विकास कार्य केवल संबंधित वन और वन्यजीव कानूनों के तहत विशेष अनुमति से ही संभव होता।

अरावली का महत्व क्या है?

अरावली पर्वतमाला दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल रिचार्ज, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि यहां अनियंत्रित खनन "देश की पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा" है।

अब आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद यथास्थिति कायम हो गई है। अदालत अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर तय करेगी कि अरावली की परिभाषा क्या हो और संरक्षण व विकास के बीच संतुलन कैसे साधा जाए।

नई परिभाषा से अरावली के बड़े हिस्से तकनीकी रूप से बाहर हो सकते हैं "पहाड़ी" की श्रेणी से

पर्यावरण कार्यकर्ताओं, विज्ञानियों और विपक्षी दलों का आरोप है कि इस नई परिभाषा से अरावली के बड़े हिस्से तकनीकी रूप से "पहाड़ी" की श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। इससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को खनन के लिए खोलने का रास्ता बन सकता है। उनका कहना है कि यह बदलाव बिना पर्याप्त वैज्ञानिक अध्ययन और जन-सलाह के किया गया।

Dainik Jagaran Page No-5

सुविधा | डिजिटल नोमैड अपनी आय विदेशी कंपनियों से हासिल करते हैं, पर उसे खर्च स्थानीय बाजार में करते हैं, इससे मुद्रा आती है

दुनियाभर में अब आम होता जा रहा खास डिजिटल नोमैड वीजा

दुनिया के कई देश अब खास डिजिटल नोमैड वीजा दे रहे हैं। महामारी के समय का यह प्रयोग अब आम हो गया है। पिछले हफ्ते बुल्गारिया भी नोमैड वीजा देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। अब रिमोट वर्क को इमिग्रेशन पॉलिसी में शामिल किया जा रहा है। नोमैड लिस्ट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 19 लाख डिजिटल नोमैड रहते हैं। वीजा के फायदे और उद्देश्य पर समीक्षा गोयल की रिपोर्ट।

19 लाख के करीब डिजिटल नोमैड रहते हैं भारत में

डिजिटल नोमैड कौन होता है

डिजिटल नोमैड उनको कहते हैं, जो किसी अलग-अलग शहरों या देशों में यात्रा करते हुए तकनीक (लैपटॉप और इंटरनेट) की मदद से अपना काम करते हैं। टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग ऐसी जगहों को चुनते हैं।

स्टैंडर्ड वीजा से कैसे अलग

टूरिस्ट वीजा छोटी यात्राओं यानी 30-90 दिनों के लिए होता है। यह सिर्फ घूमने-फिरने, दोस्तों और परिवार से मिलने के लिए होता है। इसके उलट, नोमैड वीजा कानूनी रिमोट काम के अधिकार देते हैं और दो साल या उससे ज्यादा समय तक रहने की अनुमति देते हैं।

योग्यता के क्या हैं मापदंड

अधिकतर देशों को रिमोट वर्क का सबूत चाहिए होता है। जैसे रोजगार कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांस एग्रीमेंट, या ऑनलाइन बिजनेस चलाने का पेपर जरूरी है। इसमें न्यूनतम आय 1,500-4,000 डॉलर प्रति माह होनी चाहिए। तुर्किये में तीन हजार डॉलर के साथ यूनिवर्सिटी की डिग्री भी चाहिए।

डिजिटल नोमैड वीजा बनाम पर्यटक वीजा

विशेषता	पर्यटक वीजा	डिजिटल नोमैड वीजा
अवधि	आमतौर पर 30-90 दिन	1 से 2 साल (नवीकरणीय)
काम करने का अधिकार	सख्त मनाही (अवैध)	रिमोट वर्क की अनुमति
आय स्रोत	स्थानीय बचत	विदेशी नियोक्ता व बिजनेस
स्थानीय सेवाएं	केवल पर्यटन सेवाएं	बैंकिंग, स्वास्थ्य लाभ और रेंट एग्रीमेंट की सुविधा

कौन से देश यह सुविधा दे रहे हैं

सबसे पहले वर्ष 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा, बरमूडा और क्रोएशिया ने यह वीजा देना शुरू किया। फिर जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्किये, स्पेन, ताइवान, मोल्दोवा, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, फिलीपींस भी सूची में शामिल हो गए। अब मॉरीशस, केन्या, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी ऐसा वीजा देते हैं। ग्लोबल सिटिजन सॉल्यूशंस के अनुसार, भारत डिजिटल नोमैड्स के लिए सबसे किफायती देश है। लेकिन, अभी भारत डिजिटल नोमैड वीजा नहीं देता है। mint

Hindustan Page No-18

जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए ऑर्डर में रिकॉर्ड तेजी दर्ज

रिपोर्ट : औद्योगिक उत्पादन दो साल के नए शिखर पर पहुंचा

नई दिल्ली, एजेंसी। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर दो साल के उच्च स्तर 6.7 प्रतिशत पर पहुंच गई।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक, औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) नवंबर, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर, 2023 में 11.9 प्रतिशत दर्ज किया गया था। त्योहारों से पहले देश में मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में 22 सितंबर 2025 से कटौती की गई थी। इससे जीएसटी दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई। इसके साथ एनएसओ ने अक्तूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। अक्तूबर के लिए आईआईपी वृद्धि को बढ़ाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि पिछले महीने जारी अस्थायी अनुमान 0.4% का था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2025 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन आठ प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले इसी महीने में 5.5 प्रतिशत था।

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का आम लोगों पर असर

औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की सेहत बेहतर हो रही है। इसका सीधा लाभ नौकरी, आय, व्यापार और सरकारी सेवाओं के जरिए आम आदमी तक पहुंचता है।

1 रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना

जब फैक्ट्रियां और उद्योग ज्यादा उत्पादन करते हैं, तो उन्हें अधिक मजदूर, तकनीशियन और कर्मचारियों की जरूरत होती है। नए रोजगार पैदा हो सकते हैं।

2 आमदनी और खर्च करने की क्षमता में सुधार के आसार

उद्योगों की स्थिति बेहतर होने पर वेतन में वृद्धि, ओवरटाइम और बोनस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे लोगों की खरीदने की ताकत सुधरती है।

3 सरकार की आय बढ़ने से सुविधाएं और बेहतर होंगी

उद्योगों के अच्छे प्रदर्शन से कर संग्रह बढ़ता है। सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं, जिसका फायदा लोगों को मिलता है।

4 महंगाई पर मिला-जुला असर

ज्यादा उत्पादन होने से वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे कई सामानों के दाम स्थिर रह सकते हैं। यदि कच्चा माल महंगा है या ब्याज दरें ऊंची हैं, तो महंगाई पूरी तरह कम होना जरूरी नहीं।

5 छोटे कारोबार और एमएसएमई क्षेत्र को सहारा

बड़े उद्योगों की रफ्तार बढ़ने से छोटे उद्योगों, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग और सप्लाई चेन को भी काम मिलता है। इससे स्थानीय कारोबार को फायदा होता है।

6 शेयर बाजार, निवेश पर असर

औद्योगिक उत्पादन में तेजी से बाजार में भरोसा बढ़ता है। म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश करने वालों को फायदा हो सकता है। हालांकि, असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता।

Hindustan Page No-15

स्वदेशी डिजिटल हवाई संचार प्रणाली को विकासित करने साथ आए सेना व आइआइटी

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय वायुसेना के साफ्टवेयर विकास संस्थान (एसडीआइ) ने हवाई अनुप्रयोगों के लिए एक स्वदेशी डिजिटल संचार प्रणाली के संयुक्त डिजाइन और विकास के लिए आइआइटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने, रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है।

सोमवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर एसडीआइ कमांडेंट एयर वाइस मार्शल आर. गुरुहरि, आइआइटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि और प्रवर्तक टेक्नोलाजीज फाउंडेशन के सीईओ डा एमजे शंकर रमन द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के माध्यम से वायुसेना का लक्ष्य आइआइटी मद्रास के सहयोग से नेटवर्किंग और एन्क्रिप्शन के लिए उन्नत एल्गोरिदम विकसित करना है।

- **भारतीय वायुसेना और आइआइटी मद्रास ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए**
- **आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम**

ये प्रणालियां गतिशील हवाई वातावरण में सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च-प्रदर्शन डाटा विनिमय के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो आधुनिक सैन्य अभियानों और नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए आवश्यक हैं। स्वदेशी रूप से इस तकनीक को विकसित करने का यह समझौता आयातित प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने, तकनीकी संप्रभुता को बढ़ावा देने और भारत के रक्षा बलों की परिचालन दक्षता को मजबूत करने का प्रयास है।

एयर वाइस मार्शल आर. गुरुहरि ने कहा, 'आइआइटी मद्रास के साथ यह साझेदारी महत्वपूर्ण रक्षा संचार प्रौद्योगिकियों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। अकादमिक उत्कृष्टता को परिचालन विशेषज्ञता के साथ मिलाकर हम ऐसे नवोन्मेषी, स्वदेशी समाधानों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं जो हमारी वायुसेना की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे और एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर भारत में योगदान देंगे।'

प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा, 'भारतीय वायुसेना के लिए साफ्टवेयर विकास संबंधी यह समझौता अकादमिक और रक्षा संस्थानों के बीच तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। आइआइटी मद्रास उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा में अपनी विशेषज्ञता का योगदान देकर मजबूत, स्वदेशी समाधान तैयार करने में गर्व महसूस करता है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

Dainik Jagaran Page No-3

एआइ की वक्रदृष्टि

एआइ की 'चाल' से घबराए ओपनएआइ के सीईओ सैम आल्टमैन ने किया पांच करोड़ रुपये की नौकरी का एलान, दुनिया को एआइ के बुरे प्रभावों से बचानेवाले 'हेड आफ प्रिपेयर्डनेस' की बताई जरूरत

एआइ के जनक आल्टमैन ने माना, 'भस्मासुर' साबित होने लगा है यह

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के तेजी से बढ़ते दायरे और उसके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर अब खुद ओपनएआइ के सीईओ सैम आल्टमैन चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर 'हेड आफ प्रिपेयर्डनेस' नाम के एक अहम पद के लिए भर्ती का एलान किया है, जिसका मकसद एआइ से पैदा होने वाले खतरों को समय रहते पहचानना और उनसे निपटना होगा। इस पद के लिए करीब 5.55 लाख डालर (लगभग पांच करोड़ रुपये, इक्विटी अलग से) का सालाना पैकेज प्रस्तावित किया गया है। कंपनी ने भी पहली बार खुले तौर पर माना है कि एआइ के मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतने ही गंभीर हैं, जितने तकनीकी खतरे।

सैम आल्टमैन ने साफ किया कि यह एक बेहद तनावपूर्ण जिम्मेदारी होगी। चयनित व्यक्ति को यह समझना होगा कि एआइ किस तरह खतरनाक रूप ले सकता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। उनके मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एआइ की ताकत का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन हैकरों और हमलावर इसका दुरुपयोग न कर पाएं। नया अधिकारी ओपनएआइ की जोखिम से निपटने की पूरी रणनीति संभालेगा और साइबर सुरक्षा, जैव सुरक्षा तथा खुद को बेहतर बनाने वाले एआइ सिस्टम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर खास नजर रखेगा।

- **एआइ एजेंट बन रहे नई चुनौती, साइबर हमले और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरे की चेतावनी**
- **ओपनएआइ ने माना- उन्नत एआइ माडल कंप्यूटर सुरक्षा में गंभीर कमजोरियां खोजने लगे**

सैम आल्टमैन। फाइल

बढ़ रहे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले

एआइ की तमाम खूबियों के बीच हाल के महीनों में इससे जुड़े नकारात्मक घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में एआइ चैटबाट्स की भूमिका पर सवाल उठे हैं। कुछ मामलों में आरोप लगे हैं कि एआइ की सलाह ने हिंसक घटनाओं और आत्मघाती प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। बता दें कि चैटजीपीटी को लेकर कई मुकदमे सामने आए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि एआइ चैटबाट ने किशोरों में आत्महत्या जैसे मामलों में भूमिका निभाई।

कंप्यूटर में घुसने के रास्ते खोज चुका है एआइ

आल्टमैन ने एक्स पर लिखा कि एआइ एजेंट बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। उन्होंने माना कि एआइ आधारित साइबर हथियार भविष्य में बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी कारण ओपनएआइ अब सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन पर पहले से ज्यादा जोर दे रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि एआइ एजेंट एक उभरती हुई समस्या बन चुके हैं। ओपनएआइ के अनुसार, उसके कुछ उन्नत एआइ माडल अब कंप्यूटर सुरक्षा प्रणालियों में गंभीर खामियां पहचानने लगे हैं। हाल ही में ओपनएआइ की प्रतिद्वंद्वी कंपनी एंथ्रोपिक ने दावा किया था कि चीनी हैकरों ने उसके एआइ टूल से दुनियाभर के करीब 30 संस्थानों पर साइबर हमले किए।

****

Dainik Jagaran Page No-1

तीनों सेनाओं को मिलेगी धार और रफ्तार, दुश्मन होगा लाचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आपरेशन सिंदूर के अनुभव से सीख लेते हुए सरकार ने तीनों सेनाओं को हर परिस्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमताएं बढ़ाने के लिए 79 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों के अधिग्रहण को हरी झंडी दी गई है। सरकार का मानना है कि यह कदम भारत की सेनाओं को भविष्य के प्रौद्योगिकी-आधारित युद्ध के लिए तैयार करेगा।

डीएसी द्वारा स्वीकृत उपकरणों को आधुनिक युद्ध प्रणाली के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इनसे सटीक हमले, निगरानी, ड्रोन रोधी क्षमता और बहु-आयामी सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

79 हजार करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी, मिलेंगे आधुनिक हथियार और रक्षा प्रणाली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में लिया गया फैसला

राजनाथ सिंह। फाइल

नौसेना और वायुसेना के लिए भी अहम मंजूरी

डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए बीलार्ड पुल (बीपी) टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी साफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एचएफ-एसडीआर) मैनपैक और हाई एल्टीट्यूड लांग एड्योरेंस (एचएएलई) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) को लीज पर लेने की स्वीकृति दी है। इससे नौसैनिक प्लेटफार्म को सहायता, लंबी दूरी का सुरक्षित संचार और हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर खुफिया, निगरानी और समुद्री डोमेन जागरूकता सुनिश्चित होगी। भारतीय वायुसेना के लिए आटोमैटिक टेक-आफ और लैंडिंग रिकार्डिंग सिस्टम, अस्त्र एमके-II एयर-टू-एयर मिसाइलें, लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर और स्याडस-1000 लांग-रेंज गाइडेंस किट्स को मंजूरी दी गई है। ये प्रणालियां एयरोस्पेस सुरक्षा को मजबूत करेंगी, लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता बढ़ाएंगी और पायलटों के प्रशिक्षण को सुरक्षित व लागत-प्रभावी बनाएंगी।

आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम

सरकारी बयान के अनुसार, 'ये अधिग्रहण राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करेंगे, विदेश पर निर्भरता कम करेंगे और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे।' बीते दो वर्षों में डीएसी की बैठकों में अब तक 5.57 लाख करोड़ रुपये से अधिक के नौ रक्षा सौदों को मंजूरी दी जा चुकी है, जो भारत की रक्षा तैयारियों में बड़े बदलाव का संकेत है।

कामिकेज ड्रोन पहली बार होगा शामिल

यह खरीद भारत की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास तौर पर लोइटर म्यूनिशन, जिसे सुसाइड या कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है, पहली बार भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। यह विस्फोटक से लैस ड्रोन लक्ष्य की तलाश में हवा में मंडराता है और सटीक हमला कर खुद को नष्ट कर देता है, जिससे दुश्मन को कोई प्रत्यक्ष सबूत भी नहीं मिल पाता। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम आधुनिक युद्ध में यूएवी और लो-प्लाइंग खतरों से निपटने में मदद करेंगे, जबकि अस्त्र एमके-II और स्याडस-1000 जैसे हथियार वायु सुरक्षा और सटीक हमले की क्षमता को नई ऊंचाई देंगे।

इन अहम रक्षा उपकरणों की होगी खरीद

रक्षा उपकरण	उपयोग
लोइटर म्यूनिशन सिस्टम	सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमला
लो-लेवल लाइटवेट रडार	छोटी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन/यूएएस की पहचान व ट्रैकिंग
पिनाक राकेट सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड राकेट	रेंज और सटीकता बढ़ाना
इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (एमके-II)	ड्रोन खतरों से सैन्य ठिकानों की सुरक्षा
हाई फ्रीक्वेंसी साफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एचएफ एसडीआर) मैनपैक	नौसेना के लिए सुरक्षित और आधुनिक संचार
हाई एल्टीट्यूड लांग एंड्योरेंस (एचएएलई) आरपीएएस	हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और टोह
आटोमैटिक टेक-आफ और लैंडिंग रिकार्डिंग सिस्टम	वायुसेना की उड़ान सुरक्षा और निगरानी बढ़ेगी
अस्त्र एमके-II एयर-टू-एयर मिसाइल	लंबी दूरी से दुश्मन विमानों को मार गिराने की क्षमता
तेजस लड़ाकू विमान के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर	पायलट प्रशिक्षण सुरक्षित और किफायती बनेगा
स्याडस-1000 लांग रेंज गाइडेंस किट	वायुसेना की सटीक लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी

थलसेना के लिए अत्याधुनिक सिस्टम : भारतीय सेना के लिए लोइटर म्यूनिशन सिस्टम, लो-लेवल लाइटवेट रडार, पिनाक मल्टीपल लांच राकेट सिस्टम (एमएलआरएस) के लिए लांग-रेंज गाइडेड राकेट एम्यूनिशन और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (एमके-II) की खरीद को मंजूरी दी गई है। ये प्रणालियां सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमला करने, छोटे व कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन का पता लगाने तथा युद्ध क्षेत्र और पीछे के इलाकों में सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा में मदद करेंगी।

'पिनाक' का पहला सफल परीक्षण पेज»3

Dainik Jagaran Page No-1

अब अपने अंतिम दिन गिन रहा माओवाद

माओवाद के बारे में गृह मंत्री अमित शाह की बातों का असर दिखाई दे रहा है और 182 जिलों में लगातार जारी उग्रवाद अब मात्र 11-12 जिलों में सिमटकर रह गया है। इस साल अब तक 500 से भी अधिक छोटे-बड़े नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई नामी माओवादी भी हैं। हाल ही में 1.1 करोड़ के इनामी माओवादी को अपने चार साथियों के साथ पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। याद रहे, गृह मंत्री ने कहा था कि साल 2026 के मार्च तक हम देश को माओवाद से हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे, अब उनकी यह बात सत्य होती नजर आ रही है और देश में माओवादी सोच अंतिम सांसें ले रही है। निस्संदेह, गृह मंत्री की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने जब कश्मीर से उग्रवाद खत्म करने की बात कही थी, तब उसे भी उन्होंने पूरा किया और अब माओवादी उग्रवाद की भी उन्होंने कमर तोड़ दी है।

लाल गलियारे के खत्म होने से अब सुदूर अछूते इलाकों में भी विकास के काम हो सकेंगे। इससे अंततः आदिवासियों का भला हो सकेगा।

एमएम राजावतराज, टिप्पणीकार

उन दिनों को शायद ही कोई भूल सकता है, जब भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा माओवाद को माना जाता था। साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो साफ लफ्जों में कहा था कि माओवादी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। उस समय पूरा लाल गलियारा चमक रहा था। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से माओवादी लड़ाके सक्रिय थे। सुरक्षा बलों पर हमले करना, रेलवे पटरियों को उड़ाना, इमारतों-स्कूलों को जलाना, जबरन वसूली से जुड़ी खबरें मीडिया में सुर्खियां बना करती थीं। जंगल के इन इलाकों के हजारों-लाखों लोग माओवादी लड़ाकों के चंगुल में फंसे हुए थे। मगर अब आलम यह है कि माओवाद अपने दिन गिन रहा है। यह आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर है। आंकड़ों के मुताबिक, लाल गलियारे के ज्यादातर जिले अब माओवाद से मुक्त हो चुके हैं। माओवादियों को सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे या तो अपने हथियार सौंप दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। कई माओवादियों ने आत्म-समर्पण किया है, तो कई मारे भी गए हैं। यह सब एक सुनियोजित रणनीति और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। सुरक्षा बलों को खुली छूट देकर, विकास को हथियार बनाकर और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाकर सरकार ने यह सपना साकार किया है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

ज्योति, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

माओवाद

बगावत को नया रूप लेने से रोकना होगा

भारत में माओवादी आंदोलन, जिसे नक्सलवाद के नाम से भी जाना जाता है, एक लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का प्रतीक है। यह 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह से शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में किसानों ने जमींदारों और सामंती व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाए। बेशक, माओवादियों के लड़ने के तरीके और उनकी वैचारिक लाइन पर गंभीर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष की भावना को नकारना आसान नहीं है। यह समझना चाहिए कि माओवादी आंदोलन की जड़ें भारत की सामाजिक-आर्थिक असमानता में हैं। आदिवासी इलाकों में भूमि अधिग्रहण, खनन कंपनियों का शोषण, विस्थापन और विकास का अभाव आदि ऐसे मुद्दे हैं, जिनके खिलाफ माओवादियों ने आवाज उठाई, ताकि आदिवासियों की मदद हो सके। 2004 से 2025 तक के आंकड़ों में हजारों माओवादी मारे गए, लेकिन वे लड़ते रहे।

दक्षिणपंथी खेमे माओवादियों को 'आतंकवादी' और 'देशद्रोही' कहकर खारिज करते हैं। वे सही हैं कि माओवादी हिंसा लोकतंत्र को चुनौती देती है और विकास के काम रोकती है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि माओवादियों ने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल-अस्पताल नहीं बनने दिए। मगर इन आलोचकों का नजरिया अक्सर एकतरफा होता है। वे आदिवासी शोषण पर चुप रह जाते हैं। वे माओवाद को 'चीन-प्रेरित' बताते रहते हैं, जबकि यह भारत की सामाजिक विसंगतियों का नतीजा है। बहरहाल, 2025 में माओवादी आंदोलन अपने सबसे कमजोर दौर में है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में बसवराजू जैसे शीर्ष नेता मारे गए, सैकड़ों ने आत्मसमर्पण किए। प्रभावित जिले 180 से घटकर 12 रह गए हैं। कई पूर्व माओवादी नेताओं ने माफी मांगी, कहा कि क्रांति के नाम पर आदिवासियों के साथ धोखा हुआ। यह पतन विचारधारा की विफलता दिखाता है। राज्य की रणनीति- सुरक्षा अभियान, विकास और सरेंडर नीतियां कामयाब हो रही हैं। मगर असली सवाल यह है कि माओवाद खत्म होने के बाद आदिवासी मुद्दे हल होंगे?

शुरुआती माओवादी अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, जिनको मुख्यधारा नजरअंदाज करती है। उनकी हिंसा ने आंदोलन को आत्मघाती बना दिया। सच्ची क्रांति लोकतांत्रिक तरीकों से होनी चाहिए, संघर्ष बिना हिंसा के। माओवाद का अंत एक सबक है। सरकार को अब आदिवासियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसे विद्रोह फिर न उभरें।

लक्ष्मीनारायण मुंडा, टिप्पणीकार

Hindustan Page No-12

चीन के युद्धाभ्यास ने बढ़ाया ताइवान का तनाव

बीजिंग, रायटर : चीन ने सोमवार को ताइवान के आसपास लाइव फायर युद्धाभ्यास शुरू किया। इसमें सैनिकों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और तोपखाने को तैनात किया गया। इसके कारण ताइवान का तनाव बढ़ गया है। ताइवान ने भी सैनिकों को तैनात किया है और हमले को रोकने का अभ्यास करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया।

चीन के पूर्वी थिएटर कमान ने कहा कि उसने ताइवान स्ट्रेट के उत्तर और दक्षिण-पश्चिम में बलों को केंद्रित किया है और जमीनी और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी और नकली हमले किए हैं। यह अभ्यास मंगलवार को भी जारी रहेगा और इसमें द्वीप के मुख्य बंदरगाहों की नाकाबंदी और उसे घेरने का अभ्यास शामिल होगा।

ताइवान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दर्जनों चीनी सैन्य बोट और विमान द्वीप के आसपास सक्रिय थे। उनमें से कुछ ताइवान क्षेत्र के करीब जानबूझकर आ रहे थे, जिसे इसकी तटरेखा से 24 समुद्री मील के रूप में परिभाषित किया गया है। ये अभ्यास अमेरिका द्वारा ताइवान को 11.1 अरब डालर के हथियारों की बिक्री की घोषणा के 11 दिन बाद शुरू हुए हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि बीजिंग के सैन्य अभ्यास नियमित सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों और संभावित हमले की तैयारी के बीच की रेखा को तेजी से धुंधला कर रहे हैं। यह ऐसी रणनीति है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को हमले की न्यूनतम चेतावनी देना है।

- ताइवान के आसपास लाइव फायर युद्धाभ्यास शुरू किया गया है
- ऐसे अभ्यासों से वास्तविक हमले का पता लगाना हो जाएगा कठिन

सिंचू एयर बेस से सोमवार को ताइवानी वायु सेना का एक मिराज 2000 फाइटर जेट उड़ान भरता हुआ। चीन ने सोमवार को ताइवान के आसपास "बड़े" सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं।

एक लाख हवाई यात्रियों को होगी परेशानी

ताइवान के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि सैन्य अभ्यास से मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के 100,000 से अधिक यात्री और 6,000 घरेलू हवाई यात्री प्रभावित होंगे। अधिकारी हवाई यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को खतरनाक क्षेत्रों से दूर ले जाएंगे या वैकल्पिक मार्गों की घोषणा करेंगे।

Dainik Jagaran Page No-11

जानें-समझें

शांति कानून

परमाणु ऊर्जा नीति के नए ढांचे पर शोर क्यों

जनसत्ता संवाद

शांति कानून भारत के परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी का बड़ा कदम है। सफलता इस बात पर निर्भर कर रही है कि नियमन किस तरह किया जा रहा है। आगामी दशक तय करेगा कि इससे ऊर्जा सुरक्षा का घेरा मजबूत बनता है या यह सिर्फ वादा भर रह जाता है। 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट आफ न्यूक्लिटर एनर्जी फार ट्रांस्फार्मिंग इंडिया (शांति) विधेयक को 17 दिसंबर को लोकसभा में जब पारित किया गया, तब विपक्ष ने बहिर्गमन किया था। अगले दिन राज्यसभा ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते मुहर लगा दी। सरकार का कहना है कि यह नया कानून भारत को 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। फिलहाल, देश में बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा महज तीन फीसद है।

अवसर या चुनौती

शांति कानून 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम के बाद भारत की परमाणु नीति में सबसे बड़ा सुधार है। पुराने ढांचे ने देश की रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि, परमाणु ऊर्जा की भागीदारी बिजली उत्पादन में सीमित रही। नया कानून निजी भागीदारी की अनुमति देता है ताकि परमाणु बिजली उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सके। साथ ही, संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण बना रहे। इसकी सफलता को लेकर सवाल यह है कि क्या भारत इस नए ढांचे को समय पर परियोजनाओं, भरोसेमंद नियमन और प्रभावी निर्माण में बदल पाएगा या फिर यह सुधार भी पिछली नीतियों की तरह देरी और कमजोर क्रियान्वयन का शिकार हो जाएगा।

स्वदेशी संयंत्र का सपना और जोखिम

भारत ने 2033 तक स्वदेशी 'स्माल माड्यूलर रिएक्टर' (एसएमआर) शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। अगले आठ वर्षों के दौरान वैश्विक परमाणु बाजार में तेज गतिविधि देखने को मिलेगी, जहां कई विदेशी कंपनियां अपनी पहले से परखी हुई और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एसएमआर तकनीकों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाएंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय निजी उद्योग जो ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार के लिए शीघ्र परमाणु क्षमता चाहता है, स्वाभाविक रूप से कम जोखिम वाले और तुरंत उपलब्ध विदेशी विकल्पों की ओर झुक सकता है।

(फाइल फोटो)

भारत की भूमिका भू-राजनीति में बढ़ रही है। अगर हमें वैश्विक खिलाड़ी बनना है तो हमें वैश्विक मानकों और रणनीतियों का पालन करना होगा। दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। हमने भी 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। नियामक की निष्पक्षता बनाए रखते हुए कुछ परमाणु गतिविधियों में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी।

- जितेंद्र सिंह, परमाणु ऊर्जा राज्यमंत्री

यह कदम पूरे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को बिना रोक-टोक खोल देने जैसा है। नया कानून पहले की उस व्यवस्था को हटा देता है जिसमें संचालक को उपकरण आपूर्तिकर्ता से मुआवजा वसूलने का अधिकार था। अगर कोई दुर्घटना होती है - चाहे वह खराब डिजाइन, घटिया पुर्जों या लापरवाही भरे निर्माण की वजह से हो- तब भी आपूर्तिकर्ता बच निकलेगा। हादसे में तीन हजार करोड़ की दायित्व सीमा अपर्याप्त है।

- शशि थरूर, कांग्रेस के सांसद

दायित्व की सीमा

वर्ष 2010 का परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में उभरा था। दायित्व की सीमा स्पष्ट नहीं थी इसलिए परमाणु परियोजनाएं बीमा के योग्य नहीं रह गई थी। नतीजा यह, न केवल विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत में निवेश से हिचकिचाने लगे बल्कि घरेलू निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने से बचने लगीं।

शांति कानून की धारा 16 एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह प्रावधान आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व को स्पष्ट और सीमित करता है। अब आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी तभी तय होगी जब उसका उल्लेख अनुबंध में स्पष्ट रूप से किया गया हो या यह साबित किया जा सके कि नुकसान जानबूझकर की गई लापरवाही का परिणाम है। प्रति दुर्घटना लगभग 3,000 करोड़ रुपए की दायित्व सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, इस सुधार की अपनी सीमाएं भी हैं।

अनुभव और आशंका

भारत का पिछला अनुभव इस आशंका को मजबूत करता है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परियोजना लगातार वर्षों की देरी, तकनीकी चुनौतियों और लागत बढ़ोतरी से जूझती रही है। अगर स्वदेशी एसएमआर भी समय पर विकसित और तैनात नहीं हो पाते तो तब तक भारतीय बाजार विदेशी तकनीकों से भर सकता है। इसका परिणाम केवल तकनीक आयात तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ईंधन आपूर्ति, प्रमुख उपकरणों, रखरखाव और संचालन में दीर्घकालिक निर्भरता पैदा होगी। ऐसी निर्भरता भारत के आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता के लक्ष्यों के विपरीत होगी और भविष्य में नीति विकल्पों को भी सीमित कर सकती है।

क्षमता के विस्तार का सवाल

भारत में परमाणु ऊर्जा विस्तार की सबसे बड़ी बाधा एकल-संचालक माड्यूल रहा है। एनपीसीआइएल सीमित सरकारी बजट और प्रशासनिक क्षमता के साथ काम करता है जबकि 100 गीगावाट लक्ष्य के लिए एक साथ दर्जनों रिएक्टर परियोजनाओं का प्रबंधन करना होगा। हकीकत यह है कि काकरापार, कुडनकुलम और राजस्थान जैसी परियोजनाएं वर्षों की देरी का सामना कर चुकी हैं जो दिखाता है कि अकेले एनपीसीआइएल के भरोसे तेज विस्तार संभव नहीं है। निजी भागीदारी का मतलब परमाणु संप्रभुता का निजीकरण नहीं है। संवेदनशील गतिविधियां- जैसे ईंधन संवर्धन, पुनर्प्रसंस्करण और भारी जल उत्पादन- सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगी। निजी कंपनियों को केवल बिजली उत्पादन और रिएक्टर संचालन जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में जगह दी जाएगी।

Jansatta Page No-7

शोध

विषाणु बन जाएंगे इलाज का हथियार

जनसत्ता संवाद

विषाणु सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते, बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत और संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ताजे पानी की झीलों में मौजूद विषाणुओं का गहराई से अध्ययन किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन विषाणुओं की प्रकृति, विकास और उनके पर्यावरण से संबंधों को समझना है। सबसे खास बात यह है कि ये विषाणु जानलेवा जीवाणुओं को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। कोशिश है कि ऐसे विषाणुओं की मदद से बीमारियों से लड़ने के लिए भविष्य की नई दवा बनाई जा सके।

इस अध्ययन के नतीजे प्रतिष्ठित जर्नल 'नेचर माइक्रोबायोलाजी' में प्रकाशित हुए हैं। यह अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन है, जिसमें वैज्ञानिकों ने झीलों से मिले 13 लाख से अधिक विषाणु जीनोम को दोबारा जोड़ा है। अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों के अंतरराष्ट्रीय दल ने कृत्रिम मेधा की मदद से विषाणुओं की छुपी हुई दुनिया को सामने लाने का काम किया। उन्होंने अमेरिका के मैडिसन, विस्कांसिन की एक झील से 20 साल में एकत्र किए गए 465 नमूनों का अध्ययन किया है। यह शोध पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक डीएनए आधारित निगरानी अध्ययन में से एक है।

इस खास तरीके से वैज्ञानिक यह समझ पाए कि समय और पर्यावरण में बदलाव के साथ विषाणु कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। झीलों से प्राप्त डीएनए और मेटाजीनोमिक्स नामक तकनीक से उसका विश्लेषण करके वैज्ञानिकों ने कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। विषाणु मौसम और साल के हिसाब से एक तय चक्र में आते-जाते हैं। कई विषाणु हर साल दोबारा दिखाई देते हैं, जो दर्शाता है कि उनका व्यवहार काफी अनुमानित होता है। हैरानी की बात है कि विषाणु अपने आतिथेय (होस्ट, जिस पर वे निर्भर होते हैं) का जीन चुरा सकते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शोधकर्ताओं को अध्ययन के दौरान ऐसे 578 विषाणु जीन मिले जो प्रकाश संश्लेषण और मीथेन के उपयोग जैसी जरूरी प्रक्रियाओं में मदद करते हैं।

कार्बन और अमोनियम जैसे पर्यावरणीय तत्व, जो अक्सर प्रदूषण से जुड़े होते हैं, विषाणुओं की संख्या और विविधता को प्रभावित करते हैं। यह वैसा ही है जैसे ये बाकी जीवों को प्रभावित करते हैं। इस शोध में वैज्ञानिकों ने 'फेज थेरेपी' की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया है। इसमें खास विषाणु (फेज) का उपयोग कर- के बैक्टीरिया को खत्म किया जा सकता है, जो सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं मरते। यह तकनीक उन एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी संक्रमणों के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं।

शोधकर्ताओं ने पाया है कि विषाणु सिर्फ बीमारियां ही नहीं फैलाते, बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सेहत और संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वे न सिर्फ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं बल्कि अन्य जीवों को भी सहयोग देते हैं। इस शोध का नेतृत्व कार्तिक अनंतरमण ने किया है, जो आइआइटी, मद्रास के वाधवानी स्कूल आफ डेटा साइंस एंड एआइ में विजिटिंग प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी आफ विस्कांसिन-मैडिसन (यूएस) में माइक्रोबियल और वायरल इकोलाजी के प्रोफेसर हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ताजे पानी की झीलों में मौजूद विषाणुओं का गहराई से अध्ययन किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन विषाणुओं की प्रकृति, विकास और उनके पर्यावरण से संबंधों को समझना है। खास बात यह है कि ये विषाणु जानलेवा जीवाणुओं को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। कोशिश है कि ऐसे विषाणुओं की मदद से बीमारियों से लड़ने के लिए भविष्य के लिए दवाएं बनाई जा सके।

अंटार्कटिका में नमूने लेने पहुंची शोधार्थी। (फाइल फोटो)

एतिहासिक सफर

कोलकाता में थमेगी 152 वर्ष पुरानी ट्राम की रफ्तार

सरकार ने ऐतिहासिक परिवहन सेवा को पूरी तरह समाप्त कर केवल एक छोटा हेरिटेज रूट बनाए रखने का लिया है निर्णय

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

कोलकाता की सड़कों पर डेढ़ सौ सालों से ज्यादा समय से दौड़ने वाली ट्राम की रफ्तार अब थमने वाली है। एशिया के इस सबसे पुराने ट्राम नेटवर्क को आधुनिकता की दौड़ और यातायात के बढ़ते दबाव के कारण बंद करने की तैयारी कर ली गई है। बंगाल सरकार ने इस ऐतिहासिक परिवहन सेवा को पूरी तरह समाप्त कर केवल एक छोटा हेरिटेज रूट बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए भावुक कर देने वाली है, जिनके लिए ट्राम सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि शहर की पहचान का अभिन्न हिस्सा रही है।

ट्राम का सफर 1873 में घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली बग्घियों से शुरू हुआ था, जो 1902 में बिजली से चलने वाले आधुनिक रूप में बदलीं। अपने स्वर्णिम दौर में इस नेटवर्क के पास 340 से अधिक ट्राम थीं, जो पूरे शहर को एक सूत्र में पिरोती थीं, लेकिन आज बदलते वक्त के साथ इसकी चमक फीकी पड़ गई है। अब शहर की सड़कों पर महज 10 से कम ट्राम बची हैं और अधिकांश डिपो बेचे जा चुके हैं या कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। प्रशासन का तर्क है कि धीमी गति से चलने वाली ट्राम आधुनिक महानगर के ट्रैफिक जाम और तेज रफ्तार की जरूरतों के बीच फिट नहीं बैठतीं, इसलिए अब मेट्रो और चौड़ी सड़कों पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, इस फैसले का चौतरफा विरोध भी हो रहा है। 'कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन' जैसे नागरिक समूह इस विरासत को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

कोलकाता: ट्राम के 152 वर्ष पूरे होने पर पूजा-अर्चना करतीं महिलाएं। फाइल

1873 में घोड़ों द्वारा खींचने वग्घियों से शुरू हुआ था ट्राम का सफर

1920 में बिजली से चलने वाले आधुनिक रूप में बदलीं

340 से अधिक ट्राम थीं, अपने स्वर्णिम दौर में इस नेटवर्क के पास

****

Dainik Jagaran Page No-7

सौर ऊर्जा संयंत्र का ट्रांसफार्मर चार्ज

कजरा

- कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र देश के सबसे बड़े सौर परियोजनाओं में से एक
- बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के लखीसराय स्थित कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत निकासी के लिए 132 केवी संरचण लाइन संयंत्र का 100 मेगावाट, 33/132 केवी क्षमता वाला ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक चार्ज कर दिया गया है।

ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्य बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लगातार गहन अनुश्रवण में पूरा किया गया है। कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत निकासी के लिए नए संचरण लाइन का निर्माण कर ग्रिड उपकेंद्र हवेली खड़गपुर एवं ग्रिड उपकेंद्र लखीसराय से चार्ज किया गया है। इससे इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे लोगों को लगातार और बिना रुकावट बिजली मिल सकेगी। इस सौर संयंत्र से दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी, पीक आवर में बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से निर्बाध रूप से 4 से 5 घंटे बिजली आपूर्ति हो सकेगी।

अधिकारियों ने बताया कि कजरा सोलर पावर प्लांट देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज प्रणाली की सौर ऊर्जा परियोनाओं में से एक है। इसके शुरू होने से बिहार में हरित ऊर्जा उत्पादन को नई मजबूती मिलेगी। पहले चरण के तहत 1810 करोड़ की अनुमानित लागत से 185 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ साथ 254 मेगावाट आवर की बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया गया है। इसके दूसरे चरण में 1055 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 116 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ साथ 241 मेगावाट आवर की बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है। इसको पूरा करने का लक्ष्य जनवरी 2027 है । परियोजना के पूरा होने के बाद कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 301 मेगावाट हो जाएगी।

Hindustan Page No-2

मिस बिहार का खिताब श्रेया ने आत्मविश्वास से जीता

प्रतियोगिता

- ऐसे आयोजन बिहार की छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने का मंच: मंत्री
- बीआर क्लब में आयोजित ग्रैंड फिनाले में प्रतिभागियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रेया ने मिस बिहार 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं नंदनी फर्स्ट रनर अप और मिताली सेकेंड रनर अप रहीं। आइस ब्रेकर ओसियन विजन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रविवार को बीआर क्लब में आयोजित ग्रैंड फिनाले में श्रेया ने सौंदर्य और प्रतिभा से यह प्रतिष्ठित ताज हासिल किया है।

कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बिहार की छुपी प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मालूम हो कि इस चार राउंड के फिनाले में पहला राउंड बॉलीवुड, दूसरा राउंड इंट्रोडक्शन, तीसरा राउंड फैशन राउंड और चौथा जजेज राउंड रहा। विभिन्न राउंड में सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति, आत्मविश्वास, सामाजिक मुद्दों पर विचार और रैंप वॉक को परखा गया। इसके बाद निर्णय लिया गया। निर्णायक मंडल में डॉ. अंजना गांधी शामिल रहीं, जबकि मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल और निफ्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर शादाब सामी ने विजेता और रनर अप प्रतिभागियों को क्राउन पहनाकर सम्मानित किया। प्रांजलि, सृस्टि, साक्षी, शालू, मिताली, रिमझिम, नंदनी, सेजल, आलिआ, मेघा, पायल, प्रीति, श्रेया, माहि, पालक और खुशी मिस बिहार 2025 के फाइनलिस्ट रहीं। आयोजक प्रवीण सिन्हा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर मेयर सीता साहू, पूर्व विधान पार्षद अरुण गांधी, आइस ब्रेक ओसियन विजन के डायरेक्टर कौशल किशोर समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।

Useful For Mains

अस्वीकृति के मायने

मनीष कुमार चौधरी

आमतौर पर अस्वीकार किए जाने को कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखने लगते हैं। दरअसल, अस्वीकृति का एक स्वस्थ डर अधिकांश लोगों के अंदर रहता है, लेकिन कुछ को यह जकड़ लेता है। जबकि इसे कुछ अलग तरह से भी देखा-समझा जा सकता है। स्वीकारे जाने या सफलता के बजाय अस्वीकृति पर ध्यान केंद्रित होगा, तो काम करना बहुत आसान लगेगा। 'नहीं' वास्तव में किसी और चीज के लिए 'हां' है। हमको जितने 'हां' की जरूरत है, उतने पाने के लिए हमें बहुत सारे 'नहीं' कहने पड़ते हैं। अस्वीकृति को असफलता के बजाय अवसर के रूप में देखना सीखने से जीवन के कई पहलुओं में अधिक संतुष्टि मिल सकती है। काम और व्यक्तिगत लक्ष्यों से लेकर मजबूत संबंधों तक। जैसा कि एक कहावत है, 'आप हर उस क्षण को याद करते हैं, जो आपसे छूट जाता है या फिर आप उसे गंवा देते हैं।' लेकिन चूके गए अवसर भी किसी को बेहतर निशाना लगाने में मदद कर सकते हैं। संभव है, उससे बेहतर अवसर उसे मिल जाए।

कायदा यह है कि अस्वीकृति से बचने के बजाय उससे निपटना सीखने की जरूरत है। अस्वीकृति के प्रति हमारा विरोध विकासवादी मनोविज्ञान में गहराई से निहित है। सामाजिक समूहों में खुद को सहज बना लेने से हमारा अस्तित्व सुनिश्चि होता है, इसलिए हमें सहज रूप से किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना सीखना चाहिए, जो नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। अस्वीकृति भावनाओं के साथ-साथ हमारी 'लड़ो या भागो' प्रवृत्ति को भी संसाधित करती है। अगर कोई हमको नहीं कहता है, तो दोष यह नहीं है कि उन्हें लगता है कि हम बेकार हैं या उन्हें लगता है कि हम एक बुरे व्यक्ति हैं या पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा, कोई दूसरा आशय भी हो सकता है। हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखना होगा, ताकि हम खुद को फिर से सामने ला सकें। सभी अस्वीकृतियां व्यक्तिगत नहीं होतीं। अस्वीकृति को विफलता के बजाय फिर से निर्देशित किए जाने की आवश्यकता के रूप में देखना चाहिए।

हम जितना अधिक अस्वीकृतियों से गुजरेंगे, यह उतना ही आसान होगा और आखिर हम उतना ही अधिक पाएंगे। जोखिम और यहां तक कि सीधे अस्वीकृति भी कई बार पुरस्कार प्राप्त करती है। कामयाब लोगों का इतिहास उठाकर देखा जा सकता है कि उनमें से अधिकतर को शुरुआती दौर में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है। लगभग हर प्रतिष्ठित लेखक को उनकी रचनाओं के आधार पर शुरुआती दौर में खारिज कर दिया गया था। इससे खुद को पीड़ित मानने या हार जाने पर तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन्होंने उस अस्वीकृति को ढाल बना लिया। लेखिका जेके रोलिंग की लिखी 'हैरी पाटर' को शुरुआती दौर में बारह प्रकाशकों ने सीधे-सीधे नकार दिया था। खिलाड़ी माइकल जार्डन को उनके हाई स्कूल की बास्केटबाल टीम से निकाल दिया गया था। पिछले साठ वर्षों में अधिकतर अमेरिकी राष्ट्रपति पहले किसी न किसी तरह से चुनाव हार चुके थे। मसलन, लिंडन बी जानसन, रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन, जार्ज एच डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। जाने-माने अभिनेता रहे सिल्वेस्टर स्टेलोन के मुताबिक, 'राकी' के लिए उनकी पटकथा और फिल्म का स्टार बनने की उनकी बोली को कई बार ठुकरा दिया गया था।

हालांकि अस्वीकार होना, खासकर अगर ऐसा बार-बार हो, तो कोई अच्छा अनुभव नहीं होता, लेकिन अपनी जीत-हार के अनुपात का हिसाब रखने के मायने यही है कि अस्वीकृति के बोझ तले हम दब गए हैं। शुरुआत में अस्वीकृतियां चुभती-सी महसूस होती हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ काम ही अस्वीकृत नहीं हो रहा, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी हम अस्वीकृत हो रहे हैं। मगर अस्वीकृति को दिल से लगाया जाए, तो वह आत्म-प्रताड़ना में बदल जाएगी। अस्वीकृति के कुछ तर्क हमेशा हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। कुछ भी अस्वीकार किया जा सकता है और किसी भी कारण से। हम इसके बारे में लगभग कुछ नहीं कर सकते। अस्वीकृति शिक्षाप्रद हो सकती है, लेकिन केवल तभी, जब हम सुनें कि यह हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अन्यथा हम शायद अस्वीकृति को पूरी तरह से गलत ही समझते रहेंगे।

सच यह है कि अस्वीकृति हमारे लिए एक उपकार बन सकती है। यह हमें वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हमें पता चलता है कि शायद हमारी लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों के विपरीत हमारे अपने दिमाग के बाहर एक पूरा ब्रह्मांड मौजूद है और दूसरों की राय भी हमारी राय जितनी ही मायने रखती है। अस्वीकृति हमारे संकल्प को भी दृढ़ कर सकती है, क्योंकि जितनी बार हमें अस्वीकार किया जाता है, उतनी ही अधिक दृढ़ता से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अस्वीकृति लचीलेपन की कला, असफलता से उबरने की क्षमता, एक उद्यमी मानसिकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण की शिक्षा देती है। हालांकि अस्वीकृति को एक वांछित परिणाम या सफलता की सीढ़ी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छे हालात में अस्वीकृति हमें खुद के प्रति सच्चा रहने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हम 'न' के साथ तालमेल बिठाना सीख जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे पास 'हां' कहने का मौका होगा।

दुनिया मेरे आगे

> अस्वीकृति हमारे लिए एक उपकार बन सकती है। यह हमें वस्तुनिष्ठ वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। हमें पता चलता है कि शायद हमारी लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों के विपरीत हमारे अपने दिमाग के बाहर एक पूरा ब्रह्मांड मौजूद है और दूसरों की राय भी हमारी राय जितनी ही मायने रखती है।

कृत्रिम रोशनी की चकाचौंध के खतरे

जिस कृत्रिम रोशनी को हमने अपनी सुविधा के लिए ईजाद किया था, उसके जोखिम अब बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा रोशनी हमारे शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा रही है। वैज्ञानिक अध्ययन इस गंभीर खतरे से आगाह कर रहे हैं।

रंजना मिश्रा

मानव सभ्यता के विकास की कहानी में आग के आविष्कार के बाद, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे क्रांतिकारी माना गया। इसने मनुष्य को अंधेरे पर विजय दिलाई और रात को दिन में बदल कर हमारी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। हमने शहरों को जगमग कर दिया, घरों को रोशन किया और अपनी रातों को भी दिन की तरह सक्रिय बना लिया। हम इसे विकास और आधुनिकता का नाम देते हैं, लेकिन आज यही विजय हमारी सबसे बड़ी जैविक पराजय का कारण बनती जा रही है। जिस कृत्रिम रोशनी को हमने अपनी सुविधा के लिए ईजाद किया था, वह अब एक ऐसे अदृश्य खतरे में तब्दील हो चुकी है, जो हमारे शरीर के सबसे महत्त्वपूर्ण अंगों खासकर हमारे दिल को अपना शिकार बना रही है।

हालिया वैज्ञानिक अध्ययन हमें जिस गंभीर खतरे से आगाह कर रहे हैं, वह न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि हमारी पूरी आधुनिक जीवनशैली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। रात का यह अनावश्यक प्रकाश हमारे दिल की सेहत के लिए एक धीमा जहर बन गया है। हममें से अधिकांश लोग इस खतरे से पूरी तरह अनजान हैं। हम रोशनी को सुरक्षा और सकारात्मकता से जोड़ते हैं, जबकि अंधेरे को डर से, लेकिन जीव विज्ञान की दृष्टि से हकीकत इसके ठीक विपरीत है। हाल ही में हुए व्यापक और गहन शोधों ने इस बात की पुष्टि की है कि रात के समय कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहना केवल हमारी नींद खराब नहीं करता, बल्कि यह हृदय संबंधी जानलेवा बीमारियों का सीधा और प्रमुख कारण बन रहा है। ये अध्ययन उन करोड़ों लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो यह मानते हैं कि रात में थोड़ी सी रोशनी, टीवी या फोन का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है।

आंकड़ों की बात करें, तो स्थिति बेहद भयावह नजर आती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग रात में अधिक तेज या लगातार कृत्रिम रोशनी के संपर्क में रहते हैं, उनमें दिल काम न करने का खतरा 56 फीसद तक बढ़ जाता है। चिकित्सा विज्ञान में इसे खतरनाक माना गया है। इसी तरह, दिल के दौरे का खतरा 47 फीसद तक और स्ट्रोक या अन्य जानलेवा स्थितियों का जोखिम तीस फीसद से अधिक पाया गया है। ये केवल कागजी संख्या नहीं हैं, बल्कि यह उन लाखों जिंदगियों का संकेत हैं, जो अपनी अज्ञानता के कारण समय से पहले काल के गाल में समा सकती हैं। इस शोध का सबसे अधिक चिंताजनक पहलू सामने आता है कि यह जोखिम उन लोगों में भी समान रूप से देखा गया, जो अपनी सेहत और शारीरिक गतिविधियों को लेकर बेहद सतर्क थे।

हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अच्छा और संतुलित भोजन कर रहे हैं, नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं, धूम्रपान नहीं करते और शराब से दूर रहते हैं, तो हमारा दिल पूरी तरह सुरक्षित है। मगर यह नया अध्ययन हमारी इस गलतफहमी को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि कृत्रिम रोशनी का दुष्प्रभाव उन लोगों पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया, जिनकी जीवनशैली आदर्श थी। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि रात का प्रकाश भी एक बड़ा जोखिम है। आप दिन भर

कितना भी दौड़ लें या कितना भी पौष्टिक आहार ले लें, यदि आप रात के समय अंधेरे में नहीं सोते हैं, तो आपका दिल खतरे में है। यह तथ्य स्वास्थ्य जगत में एक नए प्रतिमान को स्थापित करता है, जहां अंधेरा भी अब विटामिन और व्यायाम की तरह ही अच्छे स्वास्थ्य का एक अनिवार्य स्तंभ बन गया है। इस खतरे को समझने के लिए हमें मानव शरीर के विकासवादी इतिहास और उसकी जैविक संरचना को समझना होगा।

> हाल ही में हुए व्यापक और गहन शोधों ने इस बात की पुष्टि की है कि रात के समय कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहना केवल हमारी नींद खराब नहीं करता, बल्कि यह हृदय संबंधी जानलेवा बीमारियों का सीधा और प्रमुख कारण बन रहा है। ये अध्ययन उन करोड़ों लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो यह मानते हैं कि रात में थोड़ी सी रोशनी, टीवी या फोन का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है। आंकड़ों की बात करें, तो स्थिति बेहद भयावह नजर आती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग रात में अधिक तेज या लगातार कृत्रिम रोशनी के संपर्क में रहते हैं, उनमें दिल की बीमारी का खतरा 56 फीसद तक बढ़ जाता है।

लाखों वर्षों से मानव शरीर पृथ्वी के घूमने और सूर्य के उगने-ढलने के प्राकृतिक चक्र के साथ तालमेल बना कर विकसित हुआ है। हमारे पूर्वज दिन के उजाले में शिकार के अलावा अन्य काम करते थे और रात के अंधेरे में विश्राम करते थे। लाखों वर्षों की इस प्रक्रिया ने हमारे डीएनए में एक 'जैविक घड़ी' को स्थापित कर दिया है। यह घड़ी प्रकाश और अंधकार के संकेतों पर चलती है। जैसे ही सूरज ढलता है और कुदरती अंधेरा छाता है, हमारी आंखों के रेटिना के माध्यम से दिमाग को संदेश मिलता है कि अब काम बंद करने और आराम करने का समय है। इस संदेश के मिलते ही हमारा मस्तिष्क पीनियल ग्रंथि के जरिए 'मेलाटोनिन' नामक एक बहुत ही खास हार्मोन बनाना शुरू कर देता है। मेलाटोनिन को आम भाषा में अक्सर केवल 'नींद का हार्मोन' समझा जाता है, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक अहम होता है।

जब रात में मेलाटोनिन का स्राव होता है, तो यह हमारे शरीर के तापमान को थोड़ा कम करता है, हमारे रक्तचाप को घटाता है और दिल की धड़कन को धीमा एवं स्थिर करता है। यह वह समय होता है, जब हमारा दिल, जो दिन भर बिना रुके हजारों लीटर खून पंप करता है और हमारा मानसिक एवं शारीरिक तनाव झेलता है, वह थोड़ा सुस्ताता है और अपनी मरम्मत करता है। दिन भर की भाग-दौड़, चिंता और प्रदूषण से हमारी रक्त वाहिकाओं तथा हृदय की मांसपेशियों में जो सूक्ष्म टूट-फूट होती है, उसे ठीक करने का काम इसी अंधेरे के दौरान मेलाटोनिन की देखरेख में संभव हो पाता है। यह एक 'प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली' है, जो हमारे शरीर को अगले दिन के लिए तरोताजा करती है।

शहरीकरण ने इस समस्या को और विकराल बना दिया है। हम ऐसे शहरों में रहते हैं, जो कभी नहीं सोते और जगमगाते रहते हैं। इसे प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। पहले प्रदूषण का मतलब केवल हवा या पानी का गंदा होना था, लेकिन अब प्रकाश ने भी प्रदूषण का रूप ले लिया है, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रतिदिन नष्ट कर रहा है। वैज्ञानिक अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रात का प्रकाश मधुमेह और मोटापे जैसी चयापचय संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है, जो आगे चल कर हृदय रोगों का कारण बनते हैं। मगर इस गंभीर खतरे को टालना पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। सबसे पहले हम अपने शयनकक्ष में अंधेरे को तवज्जो दें। सुनिश्चित करें कि कमरे में किसी भी स्रोत से कोई भी रोशनी न आ पाए। सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल फोन, लैपटाप, टैबलेट और टीवी को बंद कर दें। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकने में सबसे आगे होती है।

असल में रात का अंधेरा केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और दिल के लिए एक अनिवार्य स्वास्थ्य आवश्यकता है। हमने अपनी सुविधा के लिए इस अंधेरे पर जो रोशनी थोप दी है, वह हमारे जीवन को छोटा कर सकती है। हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि जैसे अच्छा भोजन और व्यायाम जरूरी है, वैसे ही गहरी और अंधेरी नींद भी हृदय के स्वास्थ्य की कुंजी है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें रातों को फिर से प्राकृतिक रूप में अपनाना होगा। यह छोटा सा बदलाव हमारे दिल को एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का मौका दे सकता है। याद रखना चाहिए कि जब बाहर की बत्तियां बुझती हैं, तभी हमारे भीतर जीवन की लौ अपनी पूरी क्षमता से जल पाती है।

मंथन

प्रेम प्रकाश
वरिष्ठ पत्रकार

व्यवस्थागत सुधार की प्रतिबद्धता

व्यवस्थागत सुधार की पहल से देश में सर्व-समावेशी विकास का जो माडल विकसित किया गया है, वह भविष्य में देश की प्रगति को लेकर वैश्विक संस्थाओं का भरोसा बढ़ाती है

प्रतीकात्मक

सरकार के साथ काम करने वाली ढांचागत व्यवस्था के कारगर होने के लिए जरूरी है कि इसका समय-समय पर मूल्यांकन हो, जिसमें खासतौर पर उपयोगिता और उद्देश्य को कसौटी बनाया जाए। संसद में शीतकालीन सत्र में जब चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो यह बात एक बार फिर से रेखांकित हुई कि परंपरा को सीधे-सीधे प्रासंगिकता का पर्याय नहीं ठहराया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार और मूल्यांकन के साथ ढांचागत संशोधन या परिवर्तन जरूरी है। इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान दिलचस्प है। वर्ष 1985 में ओडिशा दौरे के समय उन्होंने कहा कि सरकार जब भी एक रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं।

इसमें कहीं दो मत नहीं कि सरकारी व्यवस्था में भीतर तक जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार ने गरीबी उन्मूलन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के औचित्य और प्रभाव को देश में दशकों तक प्रभावित किया है। श्रेय देना होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जिन्होंने सुशासन का विजन दिया। यहां तक कि उनके जन्मदिवस को सुशासन दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। आजाद भारत के इतिहास में यह विजन सरकार की व्यवस्था को गतिमान और कारगर बनाने की दरकार को न सिर्फ अहमियत देता है, बल्कि इसके लिए पहल की प्रस्तावना भी करता है। इस विजन की ही देन है कि केंद्र और राज्य सरकारें जहां एक तरफ अपने मंत्रालयों और विभागों को आज नए सिरे से पुनर्गठित कर रही हैं, वहीं बड़ी आबादी को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 2014 में केंद्र में जब राजग की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। अमित शाह इस मंत्रालय के पहले मंत्री बने। इसी तरह 2019 में जब दूसरी बार राजग सरकार बनी तो दो अलग-अलग मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। आज सहकारिता और जल दोनों ही क्षेत्रों में भारत दुनिया का अग्रणी देश है। देश की दो प्रमुख सहकारी संस्थाओं अमूल और इफको ने विश्व सहकारी मानिटर 2025 की वैश्विक रैंकिंग में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है।

यह सफलता दिखाती है कि एक नए विजन के साथ आगे बढ़ते भारत में लाखों किसानों व महिलाओं की जिंदगी किस तरह बदली है। इसी तरह पानी के मामले में दशकों तक भारत को सर्वाधिक भूजल का उपभोग करने वाला देश माना जाता था। पर आज भारत दुनिया में जल संरक्षण और उसके वितरण का सबसे बड़ा कार्यक्रम चलाने वाला देश ही नहीं, जल क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करने वाला दुनिया का अग्रणी देश है। यही नहीं, गरीब कल्याण या गरीबी उन्मूलन के मामले में भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के बीच कार्य करने वाला शीर्ष देश है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयी ढांचे की बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रालय या विभाग का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77 में इसका जिक्र है। मंत्रालय के कामकाज में मंत्रियों की सहायता और नीति निर्माण के लिए नौकरशाहों की बड़ी टीम होती है। इसी तरह राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल विभागों का गठन या पुनर्गठन करते हैं।

बिहार सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह कदम अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है। बिहार में पहले से कार्यरत 45 विभागों के अलावा तीन नए विभागों के गठन की मंजूरी दी। ये तीन नए विभाग हैं- युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग। नए विभागों के गठन के साथ ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता लाने के लिए तीन मौजूदा विभागों के नामों में परिवर्तन भी किया है।

भारत आज उस दौर में है जब सुशासन के साथ विकास का विजन केंद्र से लेकर राज्यों तक में एक बड़े परिवर्तन को आकार दे रहा है। यही नहीं, सहकारी संघवाद की दृष्टि के साथ इस दौरान आपसी सहयोग और समन्वय की एक स्वस्थ परंपरा भी शुरू हुई है। यह परंपरा राजनीतिक दुराग्रहों से मुक्त है। अगर ऐसा नहीं होता तो 2022 में केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव को गुजरात के मुख्यमंत्री के ई-गवर्नेंस डैशबोर्ड सिस्टम का अध्ययन करने के लिए गांधीनगर न भेजा होता। इस तरह की प्रणाली विकास कार्यों के रियल टाइम अपडेट्स के साथ सभी स्टेक होल्डर्स से संपर्क को सुनिश्चित करती है। ई-गवर्नेंस का यह माडल आज केंद्र से लेकर राज्यों तक कई स्तरों पर काम कर रहा है, बल्कि इससे सुशासन की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने वाले कई उदाहरण भी केंद्र व राज्यों के स्तर पर सामने आ रहे हैं।

Dainik Jagaran Page No-9

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

राजधर्म और बंगाली अस्मिता का द्वंद्व

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन करते हिंदू संगठन के सदस्य। फाइल

बंगाल की राजनीति में 'पड़ोसी' कभी केवल एक भौगोलिक अवधारणा नहीं रहा। वह यहां की लोक-चेतना, ऐतिहासिक स्मृतियों और चुनावी गणित का एक स्थायी तत्व रहा है। आज, जब बंगाल अगले विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तब गंगा और पद्मा के बीच बहती कड़वाहट ने राज्य की राजनीति को एक नए और जटिल मोड़ पर ला खड़ा किया है।

बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक उथल-पुथल विशेषकर मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास और फिर अमृत मंडल की हत्या और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले ने केवल मानवीय संवेदनाओं को ही नहीं झकझोरा, बल्कि बंगाल की चुनावी राजनीति में 'राष्ट्रवाद', 'धर्म' और 'क्षेत्रीय अस्मिता' के सूत्रों को आपस में उलझा दिया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच चल रही बयानबाजी अब साधारण राजनीतिक टकराव नहीं रही। यह इस प्रश्न पर केंद्रित हो गई है कि बंगाल के मतदाताओं के सामने हिंदुओं और बंगालियों का वास्तविक रक्षक कौन है।

इस टकराव के केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का वह सीधा सवाल है, जिसने भाजपा की 'हिंदू रक्षक' वाली राजनीति को चुनौती दी है। अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि यदि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कूटनीतिक शिष्टाचार के तहत बांग्लादेशी नेतृत्व से संवाद कर सकते हैं, तो बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक रूप से स्पष्ट संदेश देने से क्यों बच रहे हैं। यह सवाल केवल राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि कूटनीति और सार्वजनिक संवेदना के बीच मौजूद दूरी को उजागर करने की कोशिश है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर 'राजधर्म' से जुड़े वीडियो का संदर्भ देकर अभिषेक बनर्जी ने इस बहस को नैतिक धरातल पर ले जाने का प्रयास किया। इसके जरिए तृणमूल कांग्रेस यह संकेत देना चाहती है कि धर्म की राजनीति केवल चुनावी लाभ का औजार नहीं हो सकती।

हालांकि यह विवाद केवल सीमा पार की घटनाओं तक सीमित नहीं है। इसका दूसरा और अधिक संवेदनशील पहलू देश के अन्य राज्यों में काम करने वाले बंगाल के प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा है। ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के श्रमिक जुएल शेख की हत्या को तृणमूल कांग्रेस ने 'बंगाली अस्मिता' के सवाल से जोड़ते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा शासित राज्यों में 'बांग्ला बोलना' अब संदेह और हिंसा का कारण बनता जा रहा है। तृणमूल का दावा है कि 'घुसपैठिया' का नैरेटिव इतना विषैला हो चुका है कि उसका असर निर्दोष बंगाली मजदूरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस मामले में 'जीरो एफआइआर' दर्ज कराने और पीड़ित परिवार को मदद की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वे स्वयं को केवल बंगाल के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में रह रहे बंगालियों की संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हैं। यह रुख भाजपा के उस राष्ट्रवाद के बरक्स खड़ा किया जा रहा है, जिसमें नागरिकता और अवैध प्रवासन के सवाल केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

इस राजनीतिक संघर्ष में एक स्पष्ट विरोधाभास भी दिखाई देता है। जहां भाजपा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस अब तक मुख्यतः बयानों और प्रेस वार्ताओं तक सीमित रही है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी का यह आरोप कि तृणमूल की राजनीति हमेशा 'तुष्टीकरण' पर आधारित रही है, इसी ध्रुवीकरण को और गहरा करता है।

आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि विदेश नीति और घरेलू राजनीति का यह घालमेल बंगाल को वैचारिक रूप से दो हिस्सों में बांटने की दिशा में बढ़ रहा है। केंद्र सरकार भले ही कूटनीतिक स्तर पर सख्त संदेश दे रही हो, लेकिन राजनीति में सार्वजनिक अभिव्यक्ति अक्सर अधिक प्रभावी साबित होते हैं।

तृणमूल कांग्रेस का रुख यह दर्शाता है कि वह विदेश नीति के प्रश्न पर केंद्र के साथ खड़े होने का दावा करते हुए भी उसकी 'चुप्पी' पर सवाल उठाती रहेगी। एक ओर पार्टी हिंदू मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि भाजपा सुरक्षा के सवाल पर विफल रही है, तो दूसरी ओर भाषा और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे के सहारे 'बंगाली अस्मिता' को केंद्र में ला रही है, ताकि भाजपा के हिंदुत्व आधारित नैरेटिव को चुनौती दी जा सके। बांग्लादेश की अशांति और देश के भीतर की घटनाएं बंगाल की राजनीति के लिए एक ऐसा दर्पण बन गई हैं, जिसमें हर दल अपनी सुविधा का प्रतिबिंब देख रहा है। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या अब केवल मानवीय त्रासदियां नहीं रहीं, बल्कि चुनावी शतरंज की बिसात पर ऐसे मोहरे बन गई हैं, जो आने वाले समय की दिशा तय करेंगे।

अब यह निर्णय बंगाल के मतदाता के हाथ में है कि वह धर्म और पहचान के इस चक्रव्यूह में सुरक्षा की परिभाषा किसके साथ जोड़ता है और स्वाभिमान का अर्थ किससे निकालता है। जनता की खामोशी और उसके शोर के बीच बना संतुलन ही तय करेगा कि इस 'राजधर्म' की लड़ाई में अंततः किसकी राजनीतिक व्याख्या स्वीकार की जाती है।

Dainik Jagaran Page No-9

प्रो. एम. एल. मीणा

विभागाध्यक्ष, भूगोल, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आजकल

यूरोप की रणनीतिक अस्पष्टता और भारत

दुनिया आज शोर से नहीं, बल्कि संकेतों से बदल रही है। अब बड़ी घोषणाओं के बजाय भू-राजनीतिक सामंजस्य वैश्विक दिशा तय करता है। इसी सामंजस्य में आज यूरोप खड़ा है, थोड़ा थका हुआ, उलझा हुआ और अपने ही निर्मित ढांचों में फंसा हुआ। वहीं दूसरी ओर, इसी सामंजस्य में भारत धीरे ही सही, किंतु संतुलित और पूरी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कहानी किसी टकराव की नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है, जब एक पुराना नेतृत्व अपनी ऊर्जा खो देता है और एक नया नेतृत्व बिना किसी शोर के उभर आता है

संसाधन आधारित भू-राजनीति में यूरोप कमजोर हो रहा है, लिहाजा भारत के लिए इस मामले में आगे बढ़ने का अवसर है। फाइल

वर्तमान सदी के इस दशक के आधा समय बीतते-बीतते वैश्विक शक्ति-संतुलन जिस तेजी से बदल रहा है, उसने यूरोप की रणनीतिक स्पष्टता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। कभी विश्व राजनीति का नैतिक और संस्थागत नेतृत्व करने वाला यूरोप आज स्वयं वैचारिक थकान, आंतरिक विभाजन और नीतिगत असमंजस से जूझता दिखाई देता है। इसके विपरीत अगर भारत को देखा जाए तो वह कहीं अधिक आत्मविश्वासी, संतुलित और बहुआयामी नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। भारत अब न केवल पश्चिमी ढांचों को नए चश्मे से देख रहा है, बल्कि उनके बाहर भी एक व्यावहारिक और दीर्घकालिक वैश्विक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा है। यह बदलाव किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि यूरोप की संरचनात्मक कमजोरी और भारत की रणनीतिक परिपक्वता का संयुक्त प्रभाव है।

यूरोप की समस्या अचानक पैदा नहीं हुई। यह धीरे-धीरे बनी कई वैचारिक और भू-राजनीतिक प्रकरण का हिस्सा रही है। शीत युद्ध के बाद यूरोप ने यह मान लिया था कि इतिहास अब समाप्त हो चुका है और लोकतांत्रिक उदारवाद ही अंतिम सत्य है। इसी के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उसने रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के हाथों सौंप दी और स्वयं नैतिकता का लबादा ओढ़ लिया। लेकिन आज भू-राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और हैं। रूस दोबारा से अपनी अवस्थिति को लेकर चिंतनशील है, चीन बड़े स्तर पर उभर रहा है और पश्चिम एशिया बदल रहा है। इसी क्रम में अफ्रीका ने भी यूरोप से कई ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिनके लिए वह कम से कम अभी तो पूरी तरह तैयार नहीं है।

यूरोप की घटती विश्वसनीयता : यूरोप की रणनीतिक अस्पष्टता सबसे पहले उसकी आंतरिक राजनीति में दिखाई देती है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद यूरोपीय संघ एक साझा सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित करने में असफल रहा है। फ्रांस सामरिक स्वायत्तता की बात तो करता है, लेकिन व्यवहार में अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्रों में उसका रुख अब भी नव-उपनिवेशवादी बना हुआ है। यूरोप एक गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक संकट से भी गुजर रहा है। पश्चिमी यूरोप में नस्लीय श्रेष्ठता की प्रवृत्तियां, धार्मिक ध्रुवीकरण और प्रवासी-विरोधी राजनीति कुछ समय से काफी तेज हुई हैं। फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों में गैर-श्वेत और एशियाई समुदायों के खिलाफ संरचनात्मक भेदभाव एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है। अरब और अफ्रीकी मूल के नागरिकों के प्रति कठोर नीतियां यूरोप के उस नैतिक दावे को कमजोर करती हैं, जिसके आधार पर वह दुनिया को मानवाधिकार और लोकतंत्र का पाठ लंबे समय से पढ़ाता रहा है। यह विरोधाभास यूरोप की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा रहा है।

यूरोप की यह थकान सामरिक और संसाधन-आधारित भू-राजनीति में भी देखने को मिलती है। ऊर्जा संकट, रक्षा बजट पर बढ़ता दबाव, वृद्ध होती जनसंख्या और आर्थिक मंदी ने यूरोपीय नीति-निर्माण को प्रतिक्रियात्मक बना दिया है। परमाणु ऊर्जा को लेकर यूरोप का रुख निरंतर बदल रहा है। जहां एक ओर हरित ऊर्जा की बात होती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के नाम पर परमाणु विकल्पों को फिर से स्वीकार किया जाना अपने आप में विडंबनात्मक स्थिति है।

भारत का उभार : ऐसे समय में भारत का उभरता नेतृत्व विशेष महत्व रखता है। भू-राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत ने स्वयं को आज तक किसी एक ध्रुव या सैन्य गठबंधन तक सीमित नहीं किया है। नाटो विस्तार और पश्चिमी सैन्य संरचनाओं के बीच भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय आधार बनाया है। एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जाए तो क्वाड में मुख्य भागीदारी के बावजूद भारत ने उसे पूरी तरह सैन्य गठबंधन में बदलने से बचाया है। रूस, अमेरिका, यूरोप और वैश्विक दक्षिण सभी के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना भारत की परिपक्व भौगोलिकता आधारित कूटनीति का प्रमाण है। भारत का नेतृत्व विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय समुद्री कमीशन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत एक सहयोग-आधारित समुद्री व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।

यूरोप की तुलना में अगर भारत का दृष्टिकोण देखा जाए तो वह अधिक समावेशी और भविष्य-केंद्रित है। जहां यूरोप नस्ल, धर्म और पहचान की राजनीति में गहराई से उलझता हुआ दिखाई देता है, वहीं भारत विविधता के साथ स्थिरता का नया आयाम प्रस्तुत करता है। भारत का लोकतांत्रिक ढांचा, उसकी सामाजिक जटिलताओं के बावजूद निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है। यह कारण है कि वैश्विक दक्षिण के कई देश आज यूरोप के बजाय भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखने लगे हैं। जी 20 नेतृत्व के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा-सेटर बनने की क्षमता रखता है।

इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत यूरोप को अस्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि नए दृष्टिकोण से देख रहा है। भारत समझता है कि यूरोप एकसमान शक्ति नहीं, बल्कि विभिन्न संकटों से गुजर रहा भू-राजनीतिक क्षेत्र है। इसलिए भारत का संबंध अब यूरोप से अब ऐतिहासिक और भावनात्मक नहीं, बल्कि यथार्थवादी और हित-आधारित होना चाहिए। इस नई कहानी में भारत केवल एक सहभागी नहीं, बल्कि दिशा देने वाला पात्र बनकर उभर रहा है, एक ऐसा नेतृत्व जो न तो प्रभुत्व थोपता है और न ही जिम्मेदारी से पीछे हटता है।

अमेरिका की अपेक्षाएं और भारत की प्राथमिकताएं

रवि बिश्नोई

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नवीन घटनाक्रमों को देखें तो आज की विश्व राजनीति एक स्पष्ट संक्रमण काल से गुजर रही है। शीत युद्ध के बाद जिस एकध्रुवीय व्यवस्था का प्रभुत्व था, वह अब बहुध्रुवीय संरचना में बदल रही है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत अमेरिका और भारत के रिश्तों में दिखाई देता है। यह रिश्ता अब केवल द्विपक्षीय सहयोग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन और नए सामरिक समीकरणों से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से पता लगता है कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति है। उसका रक्षा बजट हाल के वर्षों में 850 अरब डालर से ऊपर रहा है। लेकिन शक्ति के इस विशाल आधार के बावजूद अमेरिका को रणनीतिक साझेदारों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में भारत को अपनी वैश्विक रणनीति के केंद्र में रखना उसके लिए अपरिहार्य हो गया है।

वाशिंगटन की अपेक्षाएं इसी यथार्थ से निकलती हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' की भूमिका निभाए। क्वाड के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और तकनीकी सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा हैं। हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या और स्तर दोनों बढ़े हैं, जो इस अपेक्षा को स्पष्ट करते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल शक्ति की गणना नहीं होते हैं। यहां भारत का दृष्टिकोण उदार यथार्थवाद और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 3.5 लाख करोड़ डालर से अधिक आंकी जा रही है। इसी बीच अमेरिका की एक बड़ी अपेक्षा यह है कि भारत चीन के विरुद्ध अधिक स्पष्ट भूमिका निभाए। लेकिन भारत का चीन दृष्टिकोण शुद्ध शक्ति-संतुलन से अलग है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव तो है, लेकिन भारत इसे सैन्य टकराव में बदलने से बचता रहा है। यह 'जुड़ाव के माध्यम से संघर्ष से बचना' जैसे संतुलित नीति का उदाहरण है। भारत समझता है कि दो एशियाई शक्तियों के बीच टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है।

यही संतुलन रूस के संदर्भ में भी दिखता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन भारत का रूस के साथ रक्षा सहयोग ऐतिहासिक है। भारत के कुल रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा अब भी रूसी मूल का है। इसके अलावा, ऊर्जा आयात में रूस हाल के वर्षों में भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा है। इस तरह से भारत न तो गठबंधन-आधारित विश्व व्यवस्था चाहता है और न ही पूर्ण तटस्थता। वह बहुध्रुवीयता की नीति अपनाता है, जिसका आधार अलग-अलग मुद्दों पर साझेदारों के साथ सहयोग करना है। परंतु अमेरिका की विदेश नीति अक्सर मानक-आधारित व्यवस्था की बात करती है। भारत भी नियमों का समर्थक है, लेकिन वह उन नियमों के निर्माण में समान भागीदारी चाहता है।

आज जब दुनिया फिर से ध्रुवों में बंटने की ओर बढ़ रही है, भारत का व्यवहार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है। हमारा मानना है कि स्थिरता केवल शक्ति से नहीं, संतुलन से आती है। अमेरिका की अपेक्षाएं शक्ति-केंद्रित हैं। भारत की प्राथमिकताएं स्थिरता-केंद्रित हैं। दोनों के बीच यही अंतर इस रिश्ते की जटिलता और संभावनाओं को जन्म देता है। भविष्य में अमेरिका-भारत संबंधों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वाशिंगटन भारत को एक रणनीतिक साधन की तरह देखता है या एक स्वतंत्र शक्ति की तरह। वहीं भारत इस बात पर कायम रहेगा कि साझेदारी तभी टिकाऊ होती है, जब वह दबाव नहीं, आपसी समझ पर आधारित हो। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इस नए अध्याय और बदलती भू-राजनीति में यही संतुलन निर्णायक साबित होगा।

(लेखक इंडो पैसिफिक डोमेन में वरिष्ठ शोधार्थी हैं)

पढ़ने की संस्कृति को मिले बढ़ावा

अमन सिंह गौर

पढ़ने की संस्कृति किसी भी समाज की बौद्धिक रीढ़ होती है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों में पठन संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से जो निर्णय लिया गया है, वह इसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसके तहत स्कूलों में प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध कराए जाने तथा सुबह की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन कुछ समय इन्हें पढ़ने के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को समाचारों से परिचित कराना नहीं, बल्कि उन्हें समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तथा सामाजिक परिवर्तनों से जोड़ना है। समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थी न केवल तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि भाषा की विविधता, लेखन शैली और विचार प्रस्तुति की समझ भी विकसित करेंगे। यह अभ्यास उन्हें सोचने, विश्लेषण करने और अपनी राय बनाने की क्षमता देगा। इससे विद्यार्थियों का दृष्टिकोण अधिक व्यापक होगा और वे केवल परीक्षा केंद्रित अध्ययन तक सीमित नहीं रहेंगे।

यूपी सरकार द्वारा पढ़ाई में समाचार पत्रों को शामिल करना विद्यार्थियों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में व्यावहारिक कदम है

इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि विद्यार्थियों को अखबार से कठिन शब्द चुनकर उनके अर्थ समझने और उन्हें सूचना पट पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। यह अभ्यास शब्दावली बढ़ाने के साथ-साथ आत्मविश्वास और संवाद कौशल को भी मजबूत करेगा। भाषा केवल विषय नहीं, बल्कि सोच का माध्यम है और इस तरह के प्रयास भाषा को जीवंत बनाते हैं। पठन की यह आदत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए समाचार पत्र लंबे समय से विश्वसनीय स्रोत रहे हैं। यदि यह अभ्यास स्कूली जीवन से ही विकसित हो जाए, तो आगे चलकर छात्रों को अतिरिक्त दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह भी आवश्यक है कि इस पहल को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखा जाए। यदि इसे बिना रुचि और सहभागिता के लागू किया गया तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। शिक्षकों की भूमिका यहां महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, चर्चा को प्रोत्साहित करना होगा और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देनी होगी। पढ़ना तभी सार्थक होता है जब वह संवाद और चिंतन को जन्म दे। डिजिटल संसाधनों के साथ-साथ मुद्रित सामग्री का संतुलन बनाए रखना समय की आवश्यकता है। यदि बच्चे केवल स्क्रीन तक सीमित रहेंगे, तो गहन अध्ययन की परंपरा कमजोर पड़ती जाएगी।

पढ़ने की संस्कृति को पुनः स्थापित करना आज की सबसे बड़ी शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों में से एक है। यह पहल तभी सफल होगी, जब इसे निरंतरता, संवेदनशीलता और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Dainik Jagaran Page No-8

जाति निर्धारण पर नई दृष्टि

डा. ऋतु सारस्वत

अंतरजातीय विवाह के मामलों में जाति निर्धारण आसपास के तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता

कोर्ट के फैसले के बाद जाति निर्धारण पर छिड़ी बहस। फाइल

हाल में शीर्ष अदालत के एक निर्णय ने खूब सुर्खियां बटोरीं और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में उल्लेखित किया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी, भले ही उसके पिता गैर-अनुसूचित जाति समुदाय से थे। पीठ ने टिप्पणी दी कि ''मां की जाति उतनी ही महत्वपूर्ण पहचान है, जितनी पिता की।'' इस संदर्भ में 5 मार्च, 1964 और 17 फरवरी, 2002 की राष्ट्रपति अधिसूचनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मुख्य रूप से पिता की जाति और किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर व्यक्ति की आवासीय स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि था कि उसका पति विवाह के बाद से ही उसके साथ उसके माता-पिता के घर रह रहा है। इस तर्क से इस तथ्य को सुस्पष्ट करना था कि उसके बच्चों ने कभी भी उच्च जाति के कथित सामाजिक लाभों का उपभोग नहीं किया।

इससे पूर्व देश की विभिन्न अदालतों ने मां की जाति के इस्तेमाल के संबंध में जब भी निर्णय दिए तो उसका मूलभूत आधार यह रहा कि क्या बच्चे उच्च जाति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभों से वंचित रहे। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर तमाम तर्क-वितर्क के साथ अनेक आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। पहली आशंका तो यह है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के लाभ के लिए एक नई परंपरा स्थापित हो जाएगी, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। इन आशंकाओं को एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता, परंतु जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, ''हम कानून के प्रश्न को खुला रख रहे हैं। बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए?'' इस प्रश्न भरे वक्तव्य के गहरे निहितार्थ हैं, परंतु त्वरित रूप से निर्णय पर पहुंचने से पूर्व इस विषय पर एक गहन विमर्श की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय इस बात को सामान्य सिद्धांत घोषित नहीं करता कि जाति हमेशा मां के माध्यम से ही विरासत में मिल सकती है। न ही यह निर्णय यह सिद्ध करता है कि मात्र जाति के आधार पर भविष्य में सभी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति प्रमाण पत्र दावों को बाध्यकारी रूप से स्वीकार किया जाता रहेगा।

इस मामले को अगर समझना है तो हमें उस निर्णय का भी विश्लेषण करना होगा, जो 20 जून, 2025 को बांबे उच्च न्यायालय के 'सुजल मंगला बिरवाडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले' में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और डा. नीला गोखले की खंडपीठ ने दिया था। चंभर (अनुसूचित जाति) श्रेणी के तहत जाति वैधता प्रमाण पत्र की मांग करने वाली एक छात्रा की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था, 'यद्यपि तलाक के बाद सुजल का पालन-पोषण उसकी माता ने किया, किंतु केवल अनुसूचित जाति के माता का होना जाति-आधारित लाभों का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।' कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का पालन-पोषण विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में हुआ था। उसने केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और उसे सामाजिक रूप से किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। उसकी माता की आर्थिक स्थिति और परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि ने उसके दावे को और भी कमजोर कर दिया।

गौरतलब है कि छात्रा ने अपने पिता के गैर-अनुसूचित जाति 'हिंदू कृषि' समुदाय से होने के बावजूद अपनी माता की 'चंभर' जाति के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा मांगा था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जाति-आधारित आरक्षण के लिए केवल जन्म-आधारित संबंध ही नहीं, बल्कि वास्तविक भेदभाव का प्रमाण आवश्यक है। ठीक यही विचार दृष्टि फरवरी 2025 को बांबे उच्च न्यायालय के ही 'स्वानुभूति जीवराज जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में सामने आई। इस मामले में न्यायालय ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए यह कहा था कि जातिगत वैधता विवादों से संबंधित कानून को स्पष्ट करते हुए विभिन्न जातियों के माता-पिता से जन्मे बच्चे, जिनमें से माता या पिता में से कोई एक अनुसूचित जाति से संबंधित हों, बिना यह साबित किए कि उन्हें उस जाति से संबंधित वास्तविक सामाजिक भेदभाव, नुकसान या अभाव का सामना करना पड़ा है, स्वतः ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकते।

रमेशभाई दभाई नाइका बनाम गुजरात राज्य (2012) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अंतरजातीय विवाह के मामलों में जाति निर्धारण आसपास के तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वास्तव में यह एक तथ्य है कि कई बार परिवेश बहुत असर डालने वाला साबित होता है। जातिगत आरक्षण पर होने वाली बहस के बीच सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय अनेक आशंकाओं को जन्म दे रहा है। चूंकि इस सत्य से इन्कार नहीं कि भारत के सुदूर हिस्सों में आज भी सामाजिक ढांचा जातिगत भेदभाव के बीच गुंथा हुआ है और अनेक बार जातिगत भेदभाव की अनचाही पीड़ाएं गहरे घाव कर जाती हैं, इसलिए ऐसे गंभीर मुद्दों पर गहन विमर्श के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

नए वर्ष के निर्णायक मोर्चे

डा. मनिष दाभाडे

नया वर्ष यह तय करेगा कि भारत केवल संतुलन साधने वाला देश बना रहता है या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाला शक्ति-केंद्र बनता है

अवधेश राजपूत

वर्ष 2025 को विदाई देते हुए भारत केवल एक कैलेंडर वर्ष का समापन नहीं कर रहा, बल्कि अपनी विदेश नीति के एक अत्यंत निर्णायक और चुनौतीपूर्ण चरण में कदम रख रहा है। वर्ष 2026 भारत के लिए एक सामान्य कूटनीतिक निरंतरता का वर्ष नहीं होगा, बल्कि यह वह समय होगा जब वैश्विक सत्ता-संतुलन, आर्थिक अनिश्चितता और पड़ोसी क्षेत्रों में अस्थिरता, तीनों एक साथ भारत की रणनीतिक क्षमता की परीक्षा लेंगे। आज भारत वह देश नहीं रहा, जो वैश्विक घटनाओं पर प्रतिक्रिया देता हो। वह अब एक ऐसा प्रभावशाली शक्ति-केंद्र है, जिसकी नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। 2026 में प्रवेश करते समय भारत की विदेश नीति की सबसे तात्कालिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील चुनौती अमेरिका के साथ उसके संबंध हैं। रणनीतिक स्तर पर भारत-अमेरिका संबंध मजबूत बने हुए हैं। चीन को लेकर साझा चिंताएं, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और रक्षा साझेदारी इसकी पुष्टि करते हैं, किंतु आर्थिक मोर्चे पर स्थिति कहीं अधिक जटिल है। 2025 में भारतीय निर्यात पर लगाए गए भारी अमेरिकी शुल्कों ने यह स्पष्ट कर दिया कि रणनीतिक साझेदारी अब भी आर्थिक संरक्षणवाद की गारंटी नहीं देती। यह केवल व्यापारिक नुकसान का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस व्यापक संकेत का भी है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक साझेदार के साथ-साथ एक लेन-देन आधारित आर्थिक इकाई के रूप में देख रहा है।

भारत के लिए 2026 की दहलीज पर सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अमेरिका के साथ किसी सीमित व्यापारिक समझौते की दिशा में बढ़े, बिना यह संदेश दिए कि वह आर्थिक दबाव के आगे झुकने को तैयार है। अत्यधिक नरमी भारत की वैश्विक सौदेबाजी की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है, जबकि लंबे समय तक टकराव आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब वैश्विक मांग पहले ही मंद पड़ रही है। यह संतुलन साधना आसान नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए अनिवार्य है। एक और चिंता अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संभावित पुनर्संवाद की है। यद्यपि पाकिस्तान अब अमेरिकी विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ नहीं रहा, फिर भी यदि आतंक-रोधी सहयोग या क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ सीमित सामरिक संवाद भी बढ़ाता है तो इसका प्रभाव भारत की सुरक्षा चिंताओं पर पड़ सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत-पाकिस्तान संबंधों का पुनः 'हाइफनेशन' न हो और सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय दबाव कमजोर न पड़े।

वर्ष 2026 में भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालना अवसर और चुनौती, दोनों है। ब्रिक्स अब केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच नहीं, यह विभिन्न भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं और वैचारिक दृष्टिकोणों का एक जटिल समूह बन चुका है। भारत से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मंच को दिशा प्रदान करे, किंतु चीन का आर्थिक वर्चस्व और रूस की भू-राजनीतिक मजबूरियां सर्वसम्मति को सीमित करती हैं। कुछ नए सदस्य ब्रिक्स को पश्चिम-विरोधी मंच के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि भारत का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक और संतुलित है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह ब्रिक्स को वैचारिक ध्रुवीकरण से बचाते हुए विकास, वित्त, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जलवायु अनुकूलन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखे। यदि ब्रिक्स केवल बयानबाजी का मंच बनता है या पश्चिम-विरोधी राजनीति में उलझता है तो इससे भारत की ब्रिज-बिल्डर की भूमिका को गंभीर आघात पहुंचेगा।

व्यापार कूटनीति 2026 में भारत की विदेश नीति का एक और निर्णायक मोर्चा होगी। वैश्विक व्यापार व्यवस्था तेजी से खंडित हो रही है-संरक्षणवाद, औद्योगिक नीति और चुनिंदा डी-कपलिंग अब अपवाद नहीं, नई सामान्य स्थिति बन चुके हैं। ऐसे में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन गए हैं, किंतु इन वार्ताओं में श्रम मानक, पर्यावरण नियम, डाटा शासन और बाजार पहुंच जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। भारत के सामने यह भी चुनौती होगी कि वह अत्यधिक रक्षात्मक रवैये से बाहर निकले, बिना अपनी घरेलू नीति-स्वायत्तता से समझौता किए। अत्यधिक विलंब का जोखिम यह है कि भारत उन आपूर्ति शृंखलाओं से बाहर रह जाए, जो चीन के विकल्प तलाश रही हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पाकिस्तान भारत की सबसे जटिल चुनौती बना हुआ है। नियंत्रण रेखा पर शांति को किसी संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत के लिए जरूरी होगा कि वह विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखे, बिना ऐसे टकराव में फंसे, जो आर्थिक प्राथमिकताओं को नुकसान पहुंचाए।

बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। प्रस्तावित आम चुनावों से पहले ढाका में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है और बाहरी शक्तियां भी सक्रिय होती दिख रही हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा करनी होगी, बिना यह आभास दिए कि वह बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। चीन से वर्ष 2025 में संबंधों को स्थिर करने के कुछ प्रयास अवश्य हुए हैं, किंतु रणनीतिक अविश्वास गहरा बना हुआ है। नए वर्ष में भारत के सामने चुनौती यह होगी कि वह चीन के साथ प्रतिस्पर्धात्मक सह-अस्तित्व का प्रबंधन करे-न तो अनावश्यक टकराव की ओर बढ़े, न ही रणनीतिक शिथिलता दिखाए। भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं अब उसकी कूटनीतिक और रणनीतिक संरचनाओं पर भारी पड़ने लगी हैं। आने वाला वर्ष यह तय करेगा कि भारत केवल संतुलन साधने वाला देश बना रहता है या वास्तव में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाला शक्ति-केंद्र बन पाता है। 2026 में भारत को केवल अपने इरादों से नहीं, बल्कि अपने क्रियान्वयन से आंका जाएगा।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

महिला रचनाकारों और बड़ी रॉयल्टी के नाम रहा वर्ष

यहां स्कैन करें

प्रियदर्शन | वरिष्ठ पत्रकार

साल 2025 जाते-जाते एक बड़ा दुख दे गया। विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। हालांकि, इस 'नहीं रहे' वाले वाक्य के भीतर भी उनकी उपस्थिति इस सघनता से गूंजती रही कि लगा, यह विनोद कुमार शुक्ल के काव्य-कृतित्व का ही विस्तार है। हिंदी के संसार ने उन्हें बहुत मन से याद किया। उनसे कुछ पहले राजी सेठ और रामदरश मिश्र ने आंखें मूंद लीं और हिंदी की दुनिया को शोक और स्मृति के पल दिए।

वैसे, हिंदी साहित्य की दुनिया में इस साल का बड़ा हिस्सा विनोद कुमार शुक्ल की चर्चा के साथ ही निकला। जब मई में हिंद युग्म के प्रकाशक शैलेश भारतवासी ने 'संगत' के अपने इंटरव्यू में कहा कि वह विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रुपये तक की रॉयल्टी दे सकते हैं, तब हिंदी की दुनिया ने इसे अविश्वास के साथ देखा और सुना। कुछ ही महीनों के भीतर प्रकाशन ने वाकई विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख की रॉयल्टी दे डाली। इसमें बड़ा हिस्सा साल 2000 में छपे उनके उपन्यास *दीवार में एक खिड़की रहती थी* की बिक्री से आया।

साल 2025 में हिंदी साहित्य के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि जिस विनोद कुमार शुक्ल को उनके पुराने प्रकाशक तमाम वर्षों में तमाम किताबों पर एकमुश्त एक लाख रुपये तक की रॉयल्टी न दे पाए, उन्हें हिंद युग्म ने किस चमत्कार के साथ इतनी बड़ी रकम दे दी? क्या हिंदी के पारंपरिक प्रकाशक बेईमानी करते हैं या पेशेवर स्तर पर वे इतने नाकारा या नाकाम रहे हैं कि अपने लेखकों को ठीक से उनका दाय तक नहीं दिला सकते? इस सवाल को फिलहाल यहीं स्थगित करते हैं, क्योंकि इसका ओर-छोर ठीक से समझ में नहीं आता।

साल के अंतिम दिनों में राजकमल प्रकाशन ने साल 2025 को 'हिंदी उपन्यास का स्त्री-वर्ष' घोषित करते हुए एक साथ नौ महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों का लोकार्पण-आयोजन किया। इनमें गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, अनामिका, प्रत्यक्षा, वंदना राग, जया जादवानी, सुजाता, सविता भार्गव और शोभा लिंबू की कृतियां शामिल हैं। कहना न होगा, यह स्त्री स्वर इन दिनों हिंदी साहित्य का केंद्रीय स्वर बना हुआ है और साल भर आने वाली किताबें भी इसकी कुछ गवाही देती हैं। दिसंबर माह साहित्यिक चर्चाओं, हलचलों और विवादों के साथ इतना घटनापूर्ण रहा कि वह पूरे साल पर हावी रहा। इस महीने एक साथ पुस्तक मेलों की बाढ़ आ गई। एक ही तारीख पर जमशेदपुर, प्रयागराज, राजगीर, गोरखपुर, कोलकाता- सहित कई शहरों में तरह-तरह के आयोजन चल रहे थे और लेखक अलग-अलग समारोहों में आते-जाते हवाई अड्डों पर एक-दूसरे से मिल रहे थे।

साल की शुरुआत में ही कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को मिले बुकर पुरस्कार ने सबका ध्यान उनके लेखन की ओर खींचा।

इसी दिसंबर में साहित्य अकादेमी पुरस्कारों की घोषणा जिस तरह से टाली गई, उसने भी एक बड़ी चर्चा पैदा की। इस घोषणा के लिए 18 दिसंबर को दोपहर तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पत्रकार पहुंच भी गए, पर बिल्कुल अंतिम समय में घोषणा टाल दी गई। पता चला, अकादेमी ने निर्णय के लिए संस्कृति मंत्रालय से मशविरा नहीं किया था। साहित्य अकादेमी का अपयश पुराना है, उसकी स्वायत्तता के आत्मसमर्पण की कहानी इस प्रकरण के साथ अपने चरम पर दिखी। साल की शुरुआत में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को मिले अंतरराष्ट्रीय बुकर ने सबका ध्यान उनके लेखन की ओर खींचा। उनके संग्रह *हार्ट लैंप* की कहानियां आम मुस्लिम घर-परिवारों की ऐसी सरल-सहज दास्तानें हैं, जिनमें बुनी हुई स्त्री-कथाएं एक अलग आयाम से हमारा परिचय कराती हैं। इस साल सबसे अधिक चर्चा जिस कृति ने बटोरी, वह अरुंधति रॉय की अपनी मां पर केंद्रित आत्मकथात्मक कृति *मदर मैरी कम्स टु मी* रही। दुर्भाग्य से इस चर्चा का बड़ा हिस्सा कवर पर केंद्रित रहा, जिसमें सिगरेट पीती अरुंधति की तस्वीर थी, जबकि यह किताब मां-बेटी के द्वंद्वात्मक रिश्ते, जिंदगी से दो-दो हाथ करने के हौसले की मार्मिक कथा के लिहाज से भी पढ़े जाने योग्य है।

इस साल धर्मवीर भारती, अमरकांत और मोहन राकेश जैसे दिग्गज लेखकों की शतवार्षिकी पड़ी और कई पत्रिकाओं ने इन पर अपने विशेषांक समर्पित किए। फरवरी में पुस्तक मेले में लगी किताबों की झड़ी के साथ साल शुरू हुआ और अब 2026 जनवरी के पुस्तक मेले के लिए किताबों की नई खेप तैयार की जा रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कामयाबी

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

सिंहावलोकन- 2025

यदि पूरे साल की किसी एक उपलब्धि को रेखांकित करें, तो देश के लगभग सौ जिलों में चार दशकों से जारी सशस्त्र वामपंथी संघर्ष के अंत के आसार अब दिखने लगे हैं।

साल 2025 के समापन की ओर बढ़ने के साथ ही स्वाभाविक रूप से विश्व और भारत के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में आई चुनौतियों की पिछले वर्षों से तुलना और आने वाले वर्ष के गर्भ में छिपी संभावनाओं का लेखा-जोखा चल रहा है। कानून और शांति-व्यवस्था एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिससे जुड़ी साल भर की घटनाओं का सिंहावलोकन दिलचस्प होगा।

इस साल की शुरुआत ऐसी दुर्घटना से हुई, जिसके चलते एक बड़ी उपलब्धि का आस्वादन करता देश कुछ देर के लिए ठिठक सा गया। प्रयागराज में हर बारह साल बाद लगने वाले कुंभ मेले के दौरान भगदड़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की अकाल मृत्यु हो गई। यद्यपि मौत की संख्या के सरकारी और गैर-सरकारी दावों में बड़ा फर्क है, पर यह कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के स्नान का जश्न मनाते राष्ट्र की खुशी में खलल जरूर पड़ गया।

यदि पूरे साल की किसी एक उपलब्धि को रेखांकित करना हो, तो उस संभावना को किया जा सकता है, जिसके तहत देश के लगभग सौ जिलों में चार दशकों से भी अधिक समय से चल रहे सशस्त्र वामपंथी संघर्ष के अंत के आसार दिखने लगे हैं। आज से तीन वर्ष पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च, 2026 तक कई राज्यों में फैले माओवाद को खत्म करने की घोषणा की थी, तब सभी के मन में इस दावे को लेकर संशय था। सशस्त्र लड़ाकों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत धीमी रफ्तार से हुई, लेकिन समय के साथ इसमें तेजी आती गई। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बन गई और राज्य को मांगने पर पर्याप्त केंद्रीय पुलिस बल मिलने लगे। साल भर पुलिस के साथ माओवादियों की मुठभेड़ें और उनमें उनके नुकसान की खबरें आती रहीं। जैसे-जैसे 2025 बीतता गया, वे रक्षात्मक होते गए। वे हर दूसरे-तीसरे महीने सरकार से बातचीत और संघर्ष-

विराम की अपीलें करते रहे और सरकार उनके बिना शर्त समर्पण पर अड़ी रही। अब जब साल खत्म हो रहा है, तब यह कहा जा सकता है कि 31 मार्च, 2026 के पहले ही सशस्त्र संघर्ष द्वारा सत्ता हथियाने का माओवादी सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो सकता है। देखना है कि माओवाद के सफाये के बाद आदिवासियों से जुड़े जो मुद्दे इस संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण हो गए थे, उनसे सरकारें किस नजरिये से निपटती हैं?

यह साल एक लंबी अवधि के बाद देश में आतंकी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने के प्रयास के रूप में भी याद किया जाएगा। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम के निकट बैसरन घाटी में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया और उनमें से 26 का कत्ल कर दिया। हमलावरों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर हत्या की थी। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर घाटी में हालात तेजी से सुधर रहे थे और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों ने उधर का रुख करना शुरू कर दिया था। इससे होटल, टैक्सी, गाइड व हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो रहे थे। बेगुनाहों की हत्या का एक चमत्कारिक असर यह हुआ कि स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पूरी घाटी इन कायराना हमलों के खिलाफ खड़ी हो गई। आतंक के विरुद्ध 'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम से एक बड़ी फौजी कार्रवाई जरूर हुई, पर इस पूरे कांड ने पुलिस व्यवस्था के लिए भी कई मानीखेज सबक छोड़े। यह सवाल अनुत्तरित ही रहा कि बैसरन घाटी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल की सुरक्षा रामभरोसे कैसे छोड़ दी गई थी? दूसरी तरफ, यह एनआईए और जम्मू-कश्मीर पुलिस की सफलता मानी जाएगी कि कुछ ही दिनों में उन्होंने इस घटना में शरीक आतंकियों को ढूंढ़कर मार गिराया।

साल खत्म होते-होते देश की राजधानी एक बड़े आतंकी हमले से दहल गई। 10 नवंबर की व्यस्त शाम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के करीब लाल बत्ती पर एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी बारूद भरी कार उड़ा दी। इस दिल दहला देने वाली घटना ने आस-पास से गुजर रहे 12 निर्दोष नागरिकों की भी जान ले ली। यह विस्फोट एक बड़े षड्यंत्र का अंश था, जिसकी भनक जम्मू-कश्मीर पुलिस को कुछ ही दिनों पहले मिली थी और एक-एक करके इसके भागीदारों की गिरफ्तारियां हो ही रहीं थीं कि इसमें शरीक एक महत्वपूर्ण आतंकी ने गिरफ्तारी के डर से खुद को उड़ा दिया।

वर्षों की खामोशी के बाद हुए इस आतंकी घटनाक्रम में कई बेचैन करने वाली हकीकतें शामिल हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य तो यह है कि पूरे षड्यंत्र में मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले मेधावी छात्र शरीक थे। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत इन डॉक्टरों का मिलन केंद्र बना हरियाणा का एक निजी मेडिकल कॉलेज, जहां मुख्य आरोपी पढ़ाता था। इन अभियुक्तों के पास से जितनी मात्रा में विस्फोट सामग्री और आग्नेयास्त्र बरामद हुए थे, वे यदि समय रहते पकड़े न गए होते, तो उनसे जिस तरह का विनाश होता, उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इस तफ्तीश को आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में जम्मू-कश्मीर पुलिस के सबसे उल्लेखनीय योगदान के रूप में याद किया जाएगा।

1 जुलाई, 2024 को लागू भारतीय न्याय संहिता की सफलता को जांचने को यह पूरा वर्ष मिला। लोकसभा में गृह मंत्री ने दावा किया था कि तीन नए कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता लागू होने के बाद एफआईआर से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तीन वर्षों में तय हो जाएगा। यद्यपि एक वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं होगी, पर शुरुआती अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं कहे जाएंगे। अभी भी न्यस्त स्वार्थ अदालती कार्यवाहियों को लंबा खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि समय बीतने के साथ ये कानून किस हद तक सरकारी दावों पर खरे उतरते हैं? यह वर्ष विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के लिए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के रूप में नई चुनौतियां लेकर आया। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चली इस कार्रवाई से सामान्यतया पुलिस का कोई संबंध नहीं होना चाहिए था, पर कुछ राज्यों ने इसे नागरिकता के प्रश्न से जोड़ दिया और साल भर पुलिस अवैध विदेशी नागरिकों को तलाशने में उलझी रही।

साल 2025 का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि जहां कई चुनौतियों ने पुलिस की कार्य दक्षता पर सवालिया निशान लगाए, वहीं इस साल कई उपलब्धियां ऐसी भी रहीं, जिनको कानून-व्यवस्था लागू करने वाले पुलिस बल याद रखना चाहेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)